mediaauditornews@gmail.com mediaauditor Epaperdainikmediaauditor.in mediaauditor वर्ष-05 अंक-195 पृष्ठ-8 मूल्य-3 रूपये

सतना
17 जुलाई 2025 गुरुवार

दैनिक मीडियाऑडीटर

सतना, रीवा से एक साथ प्रकाशित

अपनी निजी..
@ पेज 7

लद्दाख में मिनी बस खाई में गिरी, 2 की मौत

नई दिल्ली (एजेंसी)। लद्दाख के कारगिल जिले के गुमरी में बुधवार सुबह मिनी बस खाई में गिर गई। हादसे में 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अन्य 6 को हल्की चोटें आई हैं। वाहन चालक हादसे में सुरक्षित बच गया है। मिनी बस में 17 यात्री सवार थे और द्रास की ओर जा रही थी, जब अचानक रास्ते में वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और राहत टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मंगलवार को भी जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में एक मिनी बस के खाई में गिर गई थी। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई जबकि 17 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं।

महाराष्ट्र में महिला ने पुलिस अधिकारियों को हनीट्रैप में फंसाया

मुंबई (एजेंसी)। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, ठाणे के दो बड़े पुलिस अफसर ने इस महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि महिला ने उन पर झूठे बलात्कार के आरोप लगाने की धमकी देकर उनसे 40-40 लाख रुपए मांगे थे।

जब इस मामले की जांच शुरू हुई, तो पता चला कि यह सिर्फ दो अफसरों का मामला नहीं है, कई और सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाया गया है। यह महिला पहले भी 2016 में उगाही के एक मामले में पकड़ी गई थी। जांच में सामने आया कि आरोपी महिला खुद को एक जरूरतमंद महिला पुलिसकर्मी या होमगार्ड बताती थी। फिर वह इसी बहाने कई आईपीएस अफसरों, एक्साइज के अधिकारियों सहित बड़े सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाती थी। अधिकारियों का कहना है कि अभी कई और मामलों की जांच चल रही है और हो सकता है कि और भी पीड़ित सामने आएं।

यह महिला लोगों को फंसाने के लिए बेहद चालाकी से काम करती थी। वह खुद को एक परेशान पूर्व-पुलिसकर्मी या विधवा बताती थी और लोगों से मदद मांगती थी।

संसद का मानसून सत्र, बिहार वोटर लिस्ट पर विपक्ष एकजुट

नई दिल्ली (एजेंसी)। 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा को लेकर विपक्ष बड़े राजनीतिक संग्राम की तैयारी में जुट गया है। इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की पार्टियां एकजुट हो गई हैं और कांग्रेस की अगुआई में चुनाव आयोग के बहाने सरकार को घेरने की रणनीति बना रही हैं। सूत्रों के अनुसार, इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और तृणमूल कांग्रेस कार्यस्थगन प्रस्ताव लाने की तैयार कर रही हैं। यह एक संसदीय प्रक्रिया है जिसका उपयोग सदन में किसी अहम मामले पर तत्काल चर्चा करने के लिए कार्यवाही स्थगित करने के लिए किया जाता है। सरकार की सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए आम सहमति बनाने की कोशिशों के बावजूद बिहार की चुनावी सियासत बड़ी बाधा बन सकती है। सरकार के लिए राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर पर रोक नहीं लगाई है। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। सरकार मामला कोर्ट में विचाराधीन होने की ढाल लेकर सदन में पहुंचेगी।

47 दिन पहले हुई थी मानसून सत्र की घोषणा संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसकी घोषणा 47 दिन पहले ही कर दी गई थी।

अदालतों में टॉयलेट की कमी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश की अदालतों में टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधा की हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को कोर्ट ने नाराजगी जताई कि देश के 25 में से 20 हाईकोर्ट ने अब तक ये नहीं बताया कि उन्होंने टॉयलेट की सुविधा सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी 2025 को सभी हाईकोर्ट, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि हर अदालत में पुरुष, महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग-अलग टॉयलेट होने चाहिए। उचित स्वच्छता पाना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन ने आज सुनवाई के दौरान सभी हाईकोर्ट को रिपोर्ट पेश करने के लिए 8 हफ्ते का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर इस बार रिपोर्ट नहीं आई तो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को खुद सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा।

यह मामला वकील राजीब कलिता की एक जनहित याचिका से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने अदालतों में टॉयलेट की खराब स्थिति का मुद्दा उठाया है।

खराब मौसम के कारण दिल्ली में 5 फ्लाइट डायवर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली-एनसीआर में बीते एक हफ्ते से तेज बारिश जारी है। पिछले तीन दिनों से बारिश लगातार हो रही है। बुधवार को भी तेज बारिश जारी है। खराब मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने वाली इंडिगो-एअर इंडिया की 2-2 फ्लाइट जयपुर और एअर इंडिया की 1 फ्लाइट अमृतसर डायवर्ट की गईं।

राजस्थान के जयपुर में बीसलपुर बांध लगभग पूरा भर गया है। बूंदी में सेल्फी लेते वक्त जेईई स्टूडेंट झरने में बह गया, 8 घंटे बाद उसकी डेडबॉडी मिली। टोंक में बुजुर्ग नदी में डूबा, करौली में भी युवक की गंभीर नदी में डूबने से मौत हुई। राज्य में 3 दिन में 20 लोगों की मौत हुई।

मध्य प्रदेश में 18 जिलों में तेज बारिश हो रही है। आलीराजपुर में उर नदी उफान पर है। शहडोल के बाणसागर डैम के 8 गेट खोले गए। बैतूल में सतपुड़ा बांध के 5 गेट 2 फीट तक खोले गए। डिंडोरी-मंडला में तेज बारिश हुई।

यूपी के 20 से ज्यादा शहरों में बारिश जारी है। गंगापार-यमुनापार के कछारी इलाकों के 200 से ज्यादा गांव पर बाढ़ का खतरा है। प्रयागराज में 5 लाख लोग बाढ़ से परेशान हैं। शहर का सबसे बड़ा श्मशान दारागंज डूबने के कारण 13 शवों का सड़क पर अंतिम संस्कार किया गया। वाराणसी के सभी 84 घाट गंगा में डूबे हैं। 1 हजार मंदिर पूरी तरह डूब में हैं। गंगा खतरे के निशान से सिर्फ 1.56 मीटर दूर है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश जारी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का मैड्रिड में इन्वेस्ट इन एमपी बिजनेस फोरम मीट में संबोधन

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारत और स्पेन दो प्राचीन सभ्यताओं के संवाहक हैं। दोनों देशों ने नैतिक मूल्यों के आधार पर अपनी पुरा संस्कृति को आगे बढ़ाया है। दोनों देश जुड़वा भाईयों की तरह हैं। अब विकास के मामले में भी हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। संस्कृति के साथ-साथ तकनीक में भी स्पेन की एक अलग ही पहचान है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में इन्वेस्ट इन एमपी बिजनेस फोरम मीट को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश भारत का सबसे तेजी से विकासशील प्रदेश है। यहां निवेश करना निस्संदेह फायदे का सौदा है। उन्होंने निवेशकों को मध्यप्रदेश की बेजोड़ खूबियां बताते हुए कहा कि यदि आप भारत में

निवेश करने की सोच रहे हैं, तो एक बार मध्यप्रदेश अवश्य आइये, मध्यप्रदेश को भूल नहीं पाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में खनिज, पर्यटन, बड़े उद्योग, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री, तकनीकी विकास से जुड़े उद्योग स्थापित करने की अपार संभावनाएं हैं।

भारत में एमपी टूरिज्म सबसे तेजी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में भरपूर भू-संपदा उपलब्ध है, जिसमें नई तकनीक का इस्तेमाल करने से विकास की अपार संभावनाएं हैं। मध्यप्रदेश, भारत के मध्य क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हम लॉजिस्टिक सेक्टर में अग्रणी बनने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप भारत के किसी और राज्य में भी उद्योग स्थापित करते हैं, तब भी आपको मध्यप्रदेश की आवश्यकता जरूर पड़ेगी।

पहलगाम हमले के बाद आतंकियों ने जश्न मनाया

श्रीनगर (एजेंसी)। 22 अप्रैल को पहलगाम की बायसरन घाटी में आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी मारे गए थे। बगल में उनकी पत्नी ऐशन्या बैठी थीं। हमले में 26 लोग मारे गए थे। पहलगाम में 26 लोगों की हत्या के बाद आतंकियों ने मौके पर जश्न मनाया। उन्होंने खुशी मनाते हुए हवा में कई राउंड फायरिंग की। ये खुलासा राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच में हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 3 आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया।

सीडीएस बोले- विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमें कमजोर बना रही, स्वदेशी एडवांस टेक्नोलॉजी जरूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को कहा कि हम कल के हथियारों से आज की लड़ाई नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा विदेश से इम्पोर्ट की गई टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमारी युद्ध तैयारियां कमजोर करती है।

सीडीएस ने कहा कि यह हमें कमजोर बना रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें दिखाया कि हमारे लिए स्वदेशी (काउंटर-अनमैंड एरियल सिस्टम) यानी एंटी ड्रोन सिस्टम क्यों जरूरी है।

हमें अपनी सुरक्षा के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अनआर्म्ड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। अधिकतर ड्रोन्स मार गिराए गए। ये हमारे किसी भी मिलिट्री या सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके।सीडीएस ने ये बातें दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में (अनमैंड एरियल व्हीकल) और (काउंटर-अनमैंड एरियल सिस्टम) की प्रदर्शनी में कहीं।

सेना ने ड्रोन्स का क्रांतिकारी इस्तेमाल किया युद्ध में ड्रोन के इस्तेमाल पर जनरल चौहान ने कहा- मुझे लगता है कि ड्रोन्स इवॉल्यूश्नरी (विकासवादी) हैं और युद्ध में उनका इस्तेमाल बहुत क्रांतिकारी रहा है।

राहुल बोले- जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग की है। राहुल ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर कहा कि, संसद के आगामी मानसून सत्र में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बिल लाया जाए।

राहुल ने अपने लेटर में प्रधानमंत्री मोदी के पुराने दो बयानों का भी जिक्र किया। जब पीएम ने 19 मई 2024 को भुवनेश्वर में और 19 सितंबर 2024 को श्रीनगर की रैली में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की बात कही थी।

इसके अलावा राहुल ने सरकार से लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए कानून लाने का भी अनुरोध किया।

साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35ए हटाते समय जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। सरकार ने उस समय ही राज्य के हालात सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा दिया था। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुर्नगठित किया गया था।

अहमदाबाद विमान हादसे की जांच में छह ब्लाइंड स्पॉट्स

नई दिल्ली (एजेंसी)। अहमदाबाद में 12 जून को टेकऑफ के महज 32 सेकेंड के भीतर क्रैश हुई एअर इंडिया की फ्लाइट बोइंग एआई-171 की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट भले सार्वजनिक हो चुकी हो, लेकिन इसके नतीजों ने कई तीखे सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में विमानन दुर्घटना जांच ब्यूरो अपनी अंतिम रिपोर्ट को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। सूत्रों के अनुसार, जांच अब 6 ऐसे तकनीकी और प्रक्रियात्मक बिंदुओं पर केंद्रित की गई है, जिनमें कोई भी एक फैक्टर पूरे हादसे की प्रकृति बदल सकता है। दरअसल, शुरुआती रिपोर्ट में दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच 'रन' से 'कटऑफ' स्थिति में जाने को हादसे की मुख्य वजह माना गया है।मगर रिपोर्ट यह खुलासा नहीं करती कि ये स्विच पायलट ने घुमाए या किसी इलेक्ट्रोमैकेनिकल फेल्योर की वजह से ऐसा हुआ।

बंगालियों से भेदभाव पर ममता का पैदल मार्च

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को भाजपा शासित राज्यों में बंगाली बोलने वाले लोगों के साथ हो रहे कथित उत्पीड़न के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। ममता ने कहा कि बंगालियों के प्रति भाजपा के रवैये से मैं शर्मिंदा और निराश हूं। अब से मैंने तय किया है कि मैं बांग्ला में ज्यादा बोलूंगी। अगर आप मुझे डिटेंशन कैंप में रखना चाहते हैं तो रखें। यह रैली कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से धर्मतला के दोरीना क्रॉसिंग तक निकाली गई। इसमें अभिषेक बनर्जी समेत पार्टी के कई बड़े नेता इस रैली में शामिल हुए। कोलकाता के अलावा पार्टी ने राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में भी इसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। यह ऐसे समय पर हो रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के दौरे पर आने वाले हैं।

महाराष्ट्र में कपल ने चलती बस से नवजात को फेंका

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के परभणी में एक युवती ने चलती बस में बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद महिला और उसके साथ मौजूद शख्स ने नवजात को बस की खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे पथरी-सेलू रोड की है।ऋतिका ढेरे (19) नाम की महिला पुणे से परभणी जाने के लिए स्लीपर बस में अल्ताफ शेख के साथ सफर कर रही थी। शेख खुद को महिला का पति बता रहा था। यात्रा के दौरान ऋतिका को लेबर पेन शुरू हो गया।

ऋतिका ने बस में ही बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद ऋतिका और अल्ताफ ने नवजात को कपड़े में लपेटा और चलती बस से बाहर फेंक दिया। पुलिस जांच में दोनों ने बताया कि वे बच्चे का पालन-पोषण करने में असमर्थ थे, इसलिए बस से फेंक दिया था।

महाराष्ट्र विधानसभा में लुंगी-बनियान पहनकर पहुंचे विपक्ष के विधायक

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बुधवार को एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने 'लुंगी-बनियान' पहनकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन शिवसेना (शिंदे गुट) के विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा विधायक हॉस्टल की कैंटीन के कर्मचारी से मारपीट के खिलाफ किया गया। शिवसेना (उद्धव गुट) के विधान परिषद में नेता अंबादास दानवे, एनसीपी (शरद पवार गुट) के विधायक जीतेन्द्र आव्हाड समेत कई विपक्षी नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। सभी ने अपने पारंपरिक कपड़ों के ऊपर बनियान और तौलिया (लुंगी की तरह) पहनकर 'गुंडा राज' के खिलाफ नारेबाजी की। अंबादास दानवे ने कहा कि जब विधायक कैंटीन में ही मारपीट कर रहे हैं, तो इससे साफ है कि सरकार ऐसे तत्वों को संरक्षण दे रही है।

इससे पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी विधायक की आलोचना कर चुके हैं। शिवसेना (शिंदे गुट) विधायक संजय गायकवाड़ ने 8 जुलाई को खाने की क्वालिटी सही नहीं मिलने पर मुंबई के आकाशवाणी विधायक गेस्ट हाउस के केंटीन स्टाफ के साथ मारपीट की थी।

राहुल बोले- असम सीएम सबसे भ्रष्ट, उनकी आंखों में डर

कामरूप (एजेंसी)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी असम दौर परे हैं। बुधवार को उन्होंने कामरूप जिले के छायगांव में रैली की। उन्होंने कहा- हिमंत बिस्वा सरमा खुद का असम का मुख्यमंत्री नहीं, राजा समझते हैं। उन्होंने कहा- हिमंत बिस्व सरमा सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। किसी दिन उन्हें इसका हिसाब देना होगा। कुछ ही समय में कांग्रेस के बब्बर शेर उन्हें जेल पहुंचाएंगे। इसका डर उनकी आंखों में साफ दिख रहा है, क्योंकि अब न मोदी और न शाह उन्हें बचा पाएंगे।

राहुल ने कहा कि कांग्रेस अगले साल असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करेगी। सांसद गौरव गोगोई की लीडरशिप में राज्य में कांग्रेस की नई टीम है जो रिजल्ट देगी। कुछ समय पहले महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे। भाजपा ने जबरदस्त धोखाधड़ी की थी। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच के चार महीनों में एक करोड़ नए मतदाता जुड़े। हमने चुनाव आयोग से पूछा- ये लोग कहां से आए हैं, कौन हैं? हमें मतदाता सूची दिखाएं और वीडियोग्राफी उपलब्ध कराएं, लेकिन

चुनाव आयोग ने हमें आज तक मतदाता सूची नहीं दी। बल्कि उसने वीडियोग्राफी से संबंधित कानून ही बदल दिया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा- देश कि सबसे पुरानी पार्टी (कांग्रेस) को अपना सदस्य उधार देना पड़ा ताकि भाजपा राज्य में सरकार बना सके। जो व्यक्ति कांग्रेस छोड़कर भाग गया था, वह अब असम का मुख्यमंत्री है। हिमंत बिस्व सरमा 2015 में भाजपा में शामिल होने से पहले असम की कांग्रेस सरकार में मंत्री थे।

खड़गे ने कहा कि भाजपा ने असम में जिन लोगों ने लोगों के साथ अन्याय किया है, उन्हें जेल भेजा जाएगा। उन्हें अब जेलों की मरम्मत करवानी चाहिए, क्योंकि उन्हें वहीं रहना होगा।

शालाओं के बच्चों द्वारा पौधारोपण के मामले में बालाघाट प्रदेश में प्रथम

भोपाल (एजेंसी)। पर्यावरण संरक्षण के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक बनाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शालाओं में दर्ज छात्र-छात्राओं के माध्यम से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधे लगाने के निर्देश दिये गए हैं। शालाओं के बच्चों द्वारा पौधरोपण किए जाने के मामले में बालाघाट जिला मध्यप्रदेश में प्रथम स्थान पर है। कलेक्टर श्री मृणाल मीणा के मार्गदर्शन में बालाघाट जिले में इस अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस अभियान में लगाए गए पौधो की सुरक्षा के साथ ही उनके फोटो माय लाइफ ऐप पर अपलोड करने के निर्देश दिये गए हैं। इस ऐप पर फोटो अपलोड करने के बाद विद्यालय के प्राचार्य द्वारा पौधे लगाने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किये जा रहे हैं।जिला शिक्षा अधिकारी श्री अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि विभाग के निर्देशों के अनुरूप जिले की शालाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की सहभागिता से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया जा रहा है। छात्र-छात्राओं द्वारा माँ के नाम पर शाला परिसर, अपने घर एवं खेतों में पौधे लगाए जा रहे हैं। बालाघाट जिले में 15 जुलाई तक इस अभियान के अंतर्गत 1255 शालाओं के छात्र-छात्राओं द्वारा 26 हजार 913 पौधे लगाये जा चुके है। इस ऐप पर दर्ज जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश में बालाघाट जिला शालाओं के बच्चों द्वारा पौधरोपण के मामले में प्रथम स्थान पर है, जबकि बैतूल जिला 1541 शालाओं के बच्चों द्वारा लगाए गए 25 हजार 324 पौधरोपण के साथ द्वितीय स्थान पर है। इस अभियान के अंतर्गत बालाघाट जिले के स्कूलों में सेंट मेरी स्कूल बालाघाट प्रथम, सांदीपनि विद्यालय बोलेगांव द्वितीय और सांदीपनि विद्यालय कटंगी तृतीय स्थान पर है। शालाओं के बच्चों द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत लगाये जा रहे पौधों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

नशे से मुक्ति सामाजिक भागीदारी से संभव - मंत्री कुशवाहा

भोपाल (एजेंसी)। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा ने मध्यप्रदेश में 30 जुलाई तक चलाये जा रहे नशे से दूरी है जरूरी'' अभियान में प्रदेशवासियों से अपील की है कि नशा एक सामाजिक बुराई है। नशामुक्त समाज का निर्माण सामाजिक भागीदारी से ही संभव होगा।मंत्री श्री कुशवाहा ने कहा कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक ताने-बाने को भी कमजोर करता है। इस अभिशाप को जड़ से समाप्त करने के लिए समाज के हर वर्ग को एकजुट होकर कार्य करना होगा। मंत्री श्री कुशवाहा ने जन-प्रतिनिधियों, पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों और युवाओं से भी आह्वान किया कि वे नशामुक्ति अभियान को जनांदोलन का रूप दें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेशवासियों की सामूहिक इच्छाशक्ति से हम नशे पर निर्णायक विजय प्राप्त कर सकते हैं।

पीएम किसान योजना सैचुरेशन के लिये शुरू होगा अभियान

भोपाल। आयुक्त भू-अभिलेख ने बताया है कि पीएम किसान योजनासैचुरेशन के लिये प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक किसानों से संपर्क कर सेचुरेशन से शेष रह गए किसानों से कार्यवाही पूर्ण कराई जाएगी और लाभ वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। अभियान के बेहतर संचालन के लिये तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। प्रदेश में लगभग 5 लाख किसानों द्वारा ई-केवायसी एवं आधार बैंक खाता डीबीटी के लिये इनेवल करने की कार्यवाही कर ली गई है। योजना में 20 लाख से अधिक किसानों द्वारा फार्मर रजिस्ट्री बनाए जाने की कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है।

उच्च शिक्षा मंत्री परमार ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए

भोपाल (एजेंसी)। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने मंत्रालय में, उच्च शिक्षा विभाग के विभिन्न विभागीय विषयों एवं गतिविधियों की समीक्षा की। उच्च शिक्षा मंत्री श्री परमार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लंबित विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निलंबन से संबंधित गंभीर एवं अनावश्यक रूप से लंबित विभागीय प्रकरणों को, सामान्य प्रशासन के नियमानुरूप समय पर निराकृत करने के निर्देश भी दिए। श्री परमार ने जनभागीदारी समिति के नियमों का पुनर्वलोकन कर, वर्तमान परिदृश्य अनुरूप समसामयिक बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।मंत्री श्री परमार ने सार्थक ऐप पर अनुचित रूप से फर्जी उपस्थिति दर्ज करने वाले प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी और अतिथि विद्वानों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री परमार ने क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन करने को कहा। श्री परमार ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की दृष्टि से, महाविद्यालयों में एकल संकाय को बहुसंकाय में उन्नयन करने की कार्यवाही को यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन एवं आयुक्त उच्च शिक्षा श्री प्रबल सिपाहा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

ऊर्जा मंत्री तोमर नई दिल्ली में मंत्रियों के समूह और विद्युत नियामक आयोगों की बैठक में हुए शामिल

भोपाल (एजेंसी)। केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों की वित्तीय स्थिरता से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिये मंत्री समूह की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता विद्युत एवं आवास तथा शहरी मामलों के राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक ने की। बैठक में ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मध्यप्रदेश नियामक आयोग द्वारा बिजली उपभोक्ताओं के हित में लिये जा रहे निर्णयों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश में ऊर्जा विभाग द्वारा किये जा रहे नवाचारों से भी अवगत कराया। बैठक में विद्युत वितरण कम्पनियों की वित्तीय स्थिरता, पारदर्शिता एवं संचालन क्षमता को सुदृढ़ बनाने पर गहन चर्चा हुई। केन्द्रीय विद्युत राज्य मंत्री श्री नाइक ने कहा कि हमारा संकल्प है कि ऊर्जा व्यवस्था को और मजबूत, पारदर्शी और जन-हितैषी बनायें, जिससे सभी को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। बैठक में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु एवं उत्तरप्रदेश के ऊर्जा मंत्री तथा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग एवं राज्य विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्य शामिल हुए।

उप मुयमंत्री श्री शु ल ने दी श्री ब्रह्मानंद यादव को श्रद्धांजलि

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के ससुर श्री ब्रह्मानंद यादव के निधन पर उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने श्रद्धांजलि अर्पित की एवं शोक संतप्त परिजनों से भेंट कर अपनी संवेदनाएँ प्रकट कीं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि स्वर्गीय श्री यादव ने अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अनुषांगिक संगठनों के कार्य में समर्पित करते हुए राष्ट्र सेवा में योगदान दिया। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति एवं परिवार को यह दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में इंटर्नशिप कार्यक्रम सम्पन्न

भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में प्रतिवर्ष संचालित होने वाले विधि संकाय के विद्यार्थियों के लिये एक माह की इंटर्नशिप सम्पन्न हुई। यह प्रशिक्षण 16 जून से प्रारंभ हुआ था। इंटर्नशिप में देश के प्रतिष्ठित विधि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत विधि संकाय के विद्यार्थियों को मानव अधिकार एवं आयोग की कार्य-प्रणाली सहित विभिन्न विषयों पर रिसोर्स पर्सन द्वारा प्रशिक्षण दिलाया गया। इंटर्नशिप में मुख्य रूप से महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर, कॅरियर कॉलेज ऑफ लॉ भोपाल, रेनेसां लॉ कॉलेज इंदौर, एलएनसीटी यूनिवर्सिटी भोपाल, के.सी. कॉलेज मुम्बई, ईश्वर सरन डिग्री कॉलेज इलाहाबाद प्रयाग, इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ भोपाल, पीआईएमआर डीएवीवी इंदौर, बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी, आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर, गवर्मेंट पीजी स्टेट लॉ कॉलेज भोपाल और भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल के विद्यार्थियों ने भाग लिया।

मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री राजीव कुमार टंडन ने कहा कि सभी विद्यार्थियों ने पूर्ण लगन से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने पर बधाई दी। श्री टंडन ने कहा कि प्रतिवर्ष विधि विभाग के विद्यार्थियों का दो सत्रों में इंटर्नशिप कार्यक्रम कराया जाता है। मानव अधिकार आयोग के पूर्व सदस्य श्री सरबजीत सिंह ने ह्यूमन राइट्स के संदर्भ में पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया। आयोग के उप पुलिस अधीक्षक श्री राजेश गुरु ने आयोग की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।

शोध अधिकारी श्री संजय कुमार विश्वकर्मा ने कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का भ्रमण एवं अध्ययन कराया। आयोग के उप सचिव श्री डी.एस. परमार ने कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया। मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री टंडन ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र भी वितरित किये।

इंटर्नशिप में विभिन्न विषय-विशेषज्ञों द्वारा विद्यार्थियों को प्रेजेंटशन एवं प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर मानव अधिकार आयोग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

नई तकनीक से कृषि में आएगा क्रांतिकारी परिवर्तन-राज्यमंत्री कृष्णा गौर

भोपाल (एजेंसी)। नई तकनीकें न केवल समय की बचत करती हैं, बल्कि जीवन को सरल और समृद्ध भी बनाती हैं। मंगलवार को पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर एक निजी उपकरण कंपनी द्वारा संचालित परिवर्तन यात्रा के समापन अवसर पर निवास कार्यालय, भोपाल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि मशीनीकरण अब कृषि का अभिन्न अंग बन चुका है, जो किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और उनकी जीवनशैली को बेहतर बनाने में सहायक है। उन्होंने विशेष रूप से महिला किसानों की सराहना करते हुए कहा कि आज वे भी आधुनिक मशीनों को अपनाकर खेती को आसान और सशक्त बना रही हैं। पावर टूल्स और कृषि उपकरणों की निर्माता कंपनी ने परिवर्तन यात्रा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी जागरूकता फैलाने और कृषि के आधुनिकीकरण में अहम योगदान दिया है। परिवर्तन यात्रा के तहत 5100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए 35 जिलों में 1500 से अधिक किसानों से सीधा संवाद किया गया। इस पहल ने किसानों में नई तकनीकों को लेकर विश्वास और उत्साह उत्पन्न किया है। कार्यक्रम में भोपाल के पूर्व सांसद श्री आलोक संजर, उपकरण निर्माता कंपनी के एमपी एएसएम श्री अनीमेश वाघेला, एवं भोपाल के अधिकृत डीलर भी उपस्थित रहे। राज्यमंत्री ने कंपनी को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि ऐसे प्रयास किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और प्रदेश को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाएंगे।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने किया पंच-सरपंच से संवाद

भोपाल (एजेंसी)। पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंगलवार बड़वानी जिले के सेंधवा में स्थित लाइन्स कान्वेंट स्कूल के मीटिंग हॉल में पंच सरपंच संवाद कार्यक्रम में क्षेत्र के पंच एवं सरपंचों से संवाद किया। मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा पंचायती राज व्यवस्था न केवल ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक ऐसी प्रणाली है जो भारतीय लोकतंत्र को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाती है। यह स्थानीय स्तर पर शासन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है और समाज के कमजोर वर्गों को अपनी आवाज़ उठाने का अवसर प्रदान करता है। पंचायती राज का महत्व देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण है।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि ग्रामीण विकास के अपने पैमाने हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्राम स्तरों तक सड़क पहुँच सुनिश्चित करना है।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि पंचायतों में सामुदायिकता का भाव होना चाहिए और पंचायतों के लिए पाँच वर्ष के लिए कौन-से कार्य करना है यह सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि तालाब, सड़क, बांध बनाने के लिए तकनीकी को ध्यान में रखकर बनाया जाए। पंचायतों में बेहतर रिकॉर्ड रखने का कार्य दूसरी संस्था नहीं कर सकती है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि नये पंचायत भवन 3 मंजिला बनाये जा रहे हैं, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा ही बनाया जाएगा। हर पंचायत के हैंडपंप का ऑडिट हो रहा है जहाँ भी हैण्डपम्प सूख गए हैं उसे हटाकर उनके स्थान पर रिचार्ज पिट का निर्माण किया जाएगा जिससे वर्षा का जल संग्रहित किया जा सके।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक बगिया माँ के नाम'' परियोजना शुरू की जा रही है, जो कि मनरेगा के माध्यम से पूरे प्रदेश में संचालित की जाएगी। इस परियोजना के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों की 30 हजार से अधिक पात्र महिलाओं की निजी भूमि पर 30 लाख से अधिक फलदार बागवानी पौधे लगाए जाएँगे। ये बगीचे उनकी आर्थिक समृद्धि का आधार बनेंगे। इस योजना के तहत, लाभार्थियों को पौधे, उर्वरक, गड्ढे खोदने के लिए श्रम सहायता, पौधों की सुरक्षा के लिए कंटीले तारों से बाड़ और सिंचाई के लिए पानी के टैंक उपलब्ध कराए जाएँगे।

तहसीलदारों को न्यायालय और गैर न्यायालय में बांटने का विरोध

भोपाल (एजेंसी)। तहसीलदारों की पदस्थापना को लेकर मोहन कैबिनेट के एक माह पुराने फैसले का प्रदेश के तहसीलदार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस फैसले से लोगों को सुविधा मिलने की बजाय दिक्कत बढ़ेगी। कुछ जिलों में कलेक्टरों ने कैबिनेट के फैसले के आधार पर आदेश भी जारी कर दिए हैं, जिसे वापस लेने की मांग की जा रही है। ऐसा न करने पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार 21 जुलाई से काम बंद करेंगे।

कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (तहसीलदार) संघ ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार कैडर के अफसरों के बीच न्यायालयीन और गैर न्यायालयीन कार्य विभाजन का विरोध किया है। संघ ने कहा है कि अफसरों के बीच इस तरह का विभाजन किसी स्टडी, किसी समिति की सिफारिश और पारदर्शी मापदंड को अपनाए बगैर किया जा रहा है। इसका कोई ठोस और तार्किक कारण भी नहीं है। इस तरह के निर्णय से कार्यक्षमता कैसे बढ़ेगी? गैर न्यायालयीन कार्यों के लिए संभागीय मुख्यालयों के जिलों में 14 और अन्य जिलों में 8 तहसीलदार और नायब तहसीलदार चिन्हित करने का काम किस आधार पर किया गया है, यह भी इसमें स्पष्ट नहीं है।

प्रदेश के तहसीलदारों का यह भी कहना है कि इस मामले में संयुक्त परामर्शदात्री समिति से सहमति ली जानी चाहिए जो नहीं ली गई है। इस मामले में संघ को विश्वास में लिए बगैर फैसला किया गया है। संघ का आरोप है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 6 के अंतर्गत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को क्रिमिनल कोर्ट का एक वर्ग माना गया है, जिसे नियुक्त करने की शक्ति धारा 14 के अंतर्गत शासन को है। जबकि प्रमुख राजस्व आयुक्त के आदेश के पालन में कलेक्टर इस तरह के पदों पर नियुक्तियां कर रहे हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

नगर परिषद इंदरगढ़ के प्रभारी सीएमओ निलंबित

भोपाल (एजेंसी)। दतिया जिले के नगर परिषद इंदरगढ़ के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेन्द्र सिंह यादव को अपने कर्त्तव्यों में लापरवाही बरतने पर नगरीय प्रशासन विकास आयुक्त श्री संकेत भोंडवे के निर्देश पर निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संभागीय कार्यालय ग्वालियर निर्धारित किया गया है।

नगर परिषद इंदरगढ़ में तालाब का निर्माण कराया जा रहा था। निर्माण के दौरान बरसात के मौसम में तालाब में पानी का भराव हुआ। सुरक्षा उपायों में लापरवाही बरतते हुए निर्माण कार्य के दौरान रेलिंग व बेरिगेटिंग की व्यवस्था नहीं गई। व्यवस्था के अभाव में छोटी बच्चियों के डूबने की घटना हुई। इसी के साथ प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) ने अपने कार्यकाल में नियम विरूद्ध कर्मचारियों की स्थापना में प्रशासनिक कार्य किये। जांच में प्रभारी नगर पालिका अधिकारी महेन्द्र सिंह यादव दोषी पाये गये।

महिला से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार, विरोध करने पर की थी मारपीट

अनूपपुर। चचाई थाना क्षेत्र में महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को पुलिस ने राहुल उर्फ कृष्ण चंद्र मेहरा (28) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। दरअसल, बकही गांव की एक महिला ने 3 जून को थाने में शिकायत दर्ज कराई। महिला ने बताया कि उसी गांव का राहुल मेहरा दोपहर के समय उसके घर में घुस आया। उसने गलत नीयत से महिला के साथ छेड़छाड़ की। उसके विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया।

चचाई थाने में पीड़िता ने दर्ज कराई शिकायत: पीड़िता की शिकायत पर चचाई थाने में धारा 333, 74, 75(1) और 115(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच में आरोपी के खिलाफ आरोप सही पाए गए। पुलिस ने राहुल उर्फ कृष्ण चंद्र मेहरा (28) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। थाना प्रभारी सुंदरेश मरावी ने बताया कि महिला की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है।

शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय मझौली में एक दिवसीय रोजगार मेला संपन्न

एक दिवासीय रोजगार मेला में 111 विद्यार्थियों को मिला प्लेसमेंट

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा जिला रोजगार कार्यालय सीधी के निर्देशों के अनुपालन में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के त्रैमासिक कैलेंडर के अनुसार शासकीय महाविद्यालय मझौली में एक दिवसीय युवा संगम संयुक्त रूप से रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जिले के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को एक ही छत के नीचे रोजगार व स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराना था। रोजगार मेले में देश, प्रदेश एवं स्थानीय स्तर से निजी क्षेत्र की कंपनियों ने भाग लिया, जिनके प्रतिनिधि अपने कंपनियों की पूर्ण जानकारी देते हुए विद्यार्थियों का साक्षात्कार लिया। इस रोजगार मेले में ऑनलाइन एवं ऑफ्लाइन माध्यम से 279 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया, और कंपनी के एचआर के साथ सीधे बात करने का उन्हें अवसर मिला। साक्षात्कार के बाद 111 विद्यार्थियों को जॉब लेटर दिए गए।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जन भागीदारी अध्यक्ष पवन कुमार मिश्रा ने अपने उद्बोधन में प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस आयोजन से क्षेत्र के युवक युवतियों को रोजगार प्राप्त होगा तथा उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में एक अलग से लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शन किया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ गीता भारती ने चयनित विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम में कृष्ण लाल पयासी जिला पंचायत सदस्य, जिला रोजगार अधिकारी अशोक तिवारी, देवेश मिश्रा प्रभारी आजीविका मिशन, डी आर तिवारी सहायक प्रबंधक डीटीआईसी, डॉ एस आर भारती सेवानिवृत्ति ग्रंथपाल, डॉ मनोज कोल,रमाशंकर गुप्ता, अखिलेश पांडेय, प्रो बी एल सिंह आयाम, प्रो सुनील सिंह, डॉ गंगादेवी बैरागी, डॉ भावना नागेंद्र, डॉ वाहिदुननिशा, दीपक सिंह, गुलाब सिंह, संदीप कुमार कोल एवं बहुत अधिक संख्या में विद्यार्थियों ने सहभागिता कर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम का संयोजन महाविद्यालय के ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट अधिकारी डॉ संदीप कुमार शर्मा द्वारा किया गया।

आउटसोर्स नियोजन में अनियमितता पर सीएमएचओ को कारण बताओ नोटिस जारी

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बबिता खरे को अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं आउटसोर्स नियोजन में अनियमितता करते हुए कार्यादेश जारी करने के कारण नोटिस जारी की गई है। तीन दिवस के अंदर औचित्यपूर्ण जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। कलेक्टर ने बताया कि शासन द्वारा विभाग अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति की अनुसंशा के आधार पर प्रदेश की वर्तमान में स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाओं (उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिविल अस्पताल एवं जिला चिकित्सालय) में मानक वर्ष 2024 के लिये पद सृजित किये गये हैं। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल मध्यप्रदेश के परिपत्र 14.10.2024 के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि राज्य स्तरीय मानक वर्ष 2024 के अनुसार प्रथम चरण में प्रदेश में स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाओं उप स्वास्थ केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिविल अस्पताल एवं जिला चिकित्सालय में आउटसोर्स के आधार पर कम्प्यूटर आपरेटर/डाटा एन्ट्री आपरेटर (आउटसोर्स) तथा मल्टी स्कील्ड ग्रुप डी वर्कर (आउटसोर्स) व्यक्तियों का नियोजन किया जाना है। स्वास्थ्य संस्थाओं जिला सीधी अंतर्गत स्वीकृत पद में से रिक्त पद को आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती करने के लिये शासकीय क्रय में कार्यकुशलता समयाबद्धता, मितव्ययिता पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य शासन शासकीय विभाग एवं उनके घटकों द्वारा सामग्री एवं सेवा उपार्जन हेतु मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित-2022) जारी किया गया है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीधी द्वारा जिला अस्पताल/सिविल सर्जन/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये कम्प्यूटर आपरेटर/डाटा एन्ट्री आपरेटर मल्टी स्कील्ड ग्रुप डी वर्कर आउटसोर्स आधार पर की गई।

जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग, 2023 में शिवराज सिंह ने 196 आदिवासी परिवारों को पट्टा दिया; अभी तक नहीं मिली भूमि

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। उपनी गांव में जमीन विवाद को लेकर सैकड़ों आदिवासी और हरिजन समुदाय के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने तहसीलदार गोपदबनास राकेश शुक्ला को ज्ञापन सौंपा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2023 में उपनी गांव के 196 आदिवासी और हरिजन परिवारों को पट्टा दिया था। लेकिन अभी तक इन परिवारों को जमीन पर कब्जा नहीं मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि 6 दिन पहले जब वे जमीन पर कब्जा लेने गए, तो वहां मौजूद लोगों से विवाद हो गया।

जमीन पर गांव के कुछ लोगों ने कब्जा किया: गांव के सरपंच के अनुसार यह सरकारी भूमि है। यह आदिवासी-हरिजन हित में दी गई थी। कुछ प्रभावशाली लोग निजी स्वार्थ के कारण जमीन खाली नहीं कर रहे हैं।

जमीन को लेकर कोर्ट में केस दायर: दूसरी तरफ, स्थानीय दिनेश उपाध्याय का दावा है कि इस जमीन पर उनका 30 सालों से पट्टा था। बंदोबस्त के दौरान यह हटाया गया। अब यह भूमि शासन की हो चुकी है। उन्होंने इसके खिलाफ सिविल कोर्ट में केस दायर किया है। तहसीलदार राकेश शुक्ला ने कहा कि मामले की जांच होगी। नियम के अनुसार

भारतीय किसान यूनियन टिकैत की मासिक बैठक संपन्न, किसानों ने उठाए बिजली, खाद और आवारा पशुओं के मुद्दे

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। भारतीय किसान यूनियन टिकैत की मासिक बैठक सेमरिया (जिला रीवा) में तालाब के पास संपन्न हुई। बैठक में क्षेत्रीय किसानों ने बिजली, डीएपी खाद की कमी और आवारा पशुओं की समस्याओं पर गहन चर्चा की। किसानों ने बताया कि धान की रोपाई के समय बिजली की अनियमित आपूर्ति से उन्हें भारी परेशानी हो रही है। इसके अलावा, डीएपी खाद सहकारी समितियों में उपलब्ध नहीं है और व्यापारियों द्वारा दोगुने दामों पर गुणवत्ताहीन खाद बेची जा रही है। किसान नेता महेंद्र सिंह बधरी ने आवारा पशुओं के मुद्दे पर कहा कि गौशालाएं किसानों के पशुओं को स्वीकार नहीं कर रही हैं, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है।बैठक की अध्यक्षता तहसील अध्यक्ष शिवमंगल सिंह ने की।

मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष सुग्रीव सिंह, विशिष्ट अतिथि उपाध्यक्ष अमित सिंह (लालू) और जिला संगठन प्रभारी राम हृदय अग्निहोत्री उपस्थित रहे। अन्य प्रमुख किसान नेताओं में ब्लॉक प्रवक्ता अशोक कुशवाहा, भूपेंद्र सिंह, रामराज सिंह, उमेश कुमार पाण्डेय, छोटेलाल तिवारी, चंद्रभान सिंह, विद्याविलास पाण्डेय, राजीव पाण्डेय, लालमणि पाण्डेय, देव अग्निहोत्री, राकेश तिवारी, इंद्रजीत सिंह सहित कई किसान मौजूद थे। बैठक के अंत में किसानों की समस्याओं को लेकर विद्युत प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपा गया।

जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ एवं सुपरवाइजर को प्रशिक्षण दिया गया

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के द्वारा निर्वाचन नामावली त्रुटि रहित बनाने के लिए बूथ लेबल अधिकारी का प्रशिक्षण कार्यक्रम 14 से 16 जुलाई तक विधानसभा स्तर के प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण में बीएलओ को विधिक प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन नामावली तैयार करने संबंधी प्रक्रिया घर-घर जाकर सत्यापन करना, मृत मतदाता, स्थानांतरित मतदाता दोहरी प्रविष्टि जैसी जानकारी एवं विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे में सतत अवगत कराया गया तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बी.एल.ए से समन्वय स्थापित कर फॉर्म 06, 07 एवं 08 को बीएलओ एप आदि के माध्यम से बारीकियां से भलीभांति अवगत कराया गया। साथ ही प्रशिक्षण उपरांत ई- वैल्यूएशन ऑनलाइन माध्यम से कराया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं समस्त निर्वाचन कार्य मे संलग्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

रीवा कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, फर्जी गैंगरेप-पॉक्सो मामले में तीन पत्रकार बरी

पुलिस की मनमानी पर करारा प्रहार

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। रीवा न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में तीन पत्रकारों–अमर मिश्रा, प्रद्युम्न शुक्ला और उमेश सिंह को फर्जी गैंगरेप और पॉक्सो मामले में 12 जुलाई 2025 को पूर्णतः दोषमुक्त करार दिया। यह फैसला न केवल इन पत्रकारों के लिए बड़ी राहत है, बल्कि पुलिस प्रशासन की मनमानी और कानून के दुरुपयोग पर भी करारा जवाब है। 21 मार्च 2022 को सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुई मारपीट की घटना को इन पत्रकारों ने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया था। इसकी रंजिश में एक महिला ने सिविल लाइन थाने में 23 मई 2022 को कथित तौर पर 7 फरवरी 2022 की मनगढ़ंत घटना के आधार पर इनके खिलाफ फर्जी एफआईआर (अपराध क्र. 258/22, धारा 376(2)(एन), 450, 506 भा.द.सं. और पॉक्सो) दर्ज कराई। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन और थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा के कार्यकाल में दर्ज इस मुकदमे ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए।

लंबी कानूनी लड़ाई में पत्रकारों ने हार नहीं मानी और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखा। वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेंद्र नाथ चतुर्वेदी, आनंद सिंह, अर्पित पांडेय और उनकी टीम ने उनकी पैरवी की। सुनवाई के दौरान पुलिस के आरोपों की पोल खुली, सबूतों का अभाव और जांच में खामियां सामने आईं। अंततः, न्यायालय ने सभी तथ्यों की गहन जांच के बाद तीनों पत्रकारों को निर्दोष घोषित किया। यह फैसला रीवा के न्यायिक इतिहास में मील का पत्थर है। यह न केवल पत्रकारों की बेगुनाही का प्रमाण है, बल्कि मीडिया की स्वतंत्रता पर हमले को विफल करने वाला कदम भी है। फैसले ने पुलिस प्रशासन को भी सबक दिया कि कानून का दुरुपयोग कर निर्दोषों को फंसाने की कोशिश नाकाम हो सकती है।यह ऐतिहासिक फैसला निष्पक्ष पत्रकारिता और न्यायपालिका की ताकत का प्रतीक बन गया है, जो भविष्य में ऐसी मनमानी कार्रवाइयों पर अंकुश लगाने की उम्मीद जगाता है।

कर्मचारियों 18 महीने से नहीं मिलै तीन-तीन हजार रुपए, कलेक्टर को दिया पत्र

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मध्यप्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ ने आज बुधवार को कलेक्ट्रेट में अपर कलेक्टर अंशुमान राज को पत्र सौंपा। महासंघ ने 23 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री निवास और विध्याचल भवन भोपाल में प्रदर्शन की चेतावनी दी है। सीधी जिले के सहकारिता कर्मचारियों को पिछले 18 महीनों से शासन द्वारा स्वीकृत 3000 रुपए प्रतिमाह की राशि नहीं मिली है। प्रदेश के अन्य जिलों में यह राशि कर्मचारियों को दी जा चुकी है। इसके अलावा पिछले 4-5 महीनों से वेतन का भुगतान भी नहीं हुआ है। कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों ने जोखिम उठाकर अतिरिक्त खाद्यान्न का वितरण किया था। इस दौरान स्वीकृत 26 महीने के कमीशन में से विक्रेताओं का हिस्सा अभी तक बकाया है। महासंघ का आरोप है कि नागरिक आपूर्ति निगम और जिला सहकारी बैंक ने मिलकर यह कमीशन रोक रखा है। अपर कलेक्टर अंशुमान राज ने कहा कि महासंघ का पत्र प्राप्त कर लिया गया है। इसे आगे की कार्यवाही के लिए भोपाल भेजा जाएगा।

पीएम किसान योजना सैचुरेशन के लिये शुरू होगा अभियान

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। आयुक्त भू-अभिलेख ने बताया है कि पीएम किसान योजना सैचुरेशन के लिये प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक किसानों से संपर्क कर सेचुरेशन से शेष रह गए किसानों से कार्यवाही पूर्ण कराई जाएगी और लाभ वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। अभियान के बेहतर संचालन के लिये तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। प्रदेश में लगभग 5 लाख किसानों द्वारा ई-केवायसी एवं आधार बैंक खाता डीबीटी के लिये इनेवल करने की कार्यवाही कर ली गई है। योजना में 20 लाख से अधिक किसानों द्वारा फार्मर रजिस्ट्री बनाए जाने की कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र कृषक परिवारों को वर्ष में कुल 6 हजार रूपये की राशि प्रदान की जा रही है। योजना की अनिवार्य कार्यवाही ई-केवायसी, आधार, बैंक खाता, डीबीटी केलिए इनेवल एवं फार्मर रजिस्ट्री जैसी अनिवार्य कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत ही हितग्राहियों को राशि प्राप्त होती है। योजना की 20वी किस्त का वितरण माह जुलाई 2025 में किया जाना प्रस्तावित है।

धौहनी क्षेत्र के बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाईजर को दिया गया प्रशिक्षण

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल के द्वारा जारी दिशा निर्देश के परिपालन में विधानसभा क्षेत्र 82 धौहनी में विधानसभा स्तरीय बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाईजर का प्रशिक्षण 14 जुलाई को कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय मझौली, 15 जुलाई को शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुसमी एवं 16 जुलाई को शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महुआगांव में आयोजित किया गया। जिसमे निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आर.पी. त्रिपाठी एसडीएम, नोडल अधिकारी दिलीप सिंह तहसीलदार मझौली, सहायक नोडल अधिकारी राजेश पारस तहसीलदार मडवास, धन कुमार टोप्पो नायब तहसीलदार मडवास, अमित कुमार सिंह मुख्य नगर परिषद अधिकारी मझौली, अमित कुमार दुबे नायब तहसीलदार कुसमी, अंगिरा

प्रसाद द्विवेदी बी.आर.सीसी. कुसमी, चन्द्रशेखर मिश्रा तहसीलदार सरई, अमित कुमार मिश्रा नायब तहसीलदार सरई, मास्टर ट्रेनर अमरदीप सिंह प्राचार्य, दिलीप कुमार गुप्ता उमा शि., के.एल. विश्वकर्मा प्राचार्य, संतोष कुमार तिवारी उ.मा.शि., शिवकुमार नामदेव प्राचार्य, जगदीश प्रसाद जायसवाल उ.मा.शि., बृजेश विश्वकर्मा मा.शि., रण विजय सिंह मा.शि., पी.एल. टाडिया वरि.अ., राज कुमार सिंह वरि.अ. एवं कम्प्यूटर सेवी विनय कुमार पाण्डेय ए.जी.एम. मझौली, सुचित कुमार तिवारी सहा.प्रो. निर्वाचन शाखा मझौली, कौशल किशोर प्रजापति डा.इ.आ. निर्वाचन शाखा मझौली, संजय कुमार साकेत डा.इ.आ. निर्वाचन शाखा कुसमी, सुबेदास रावत कार्यालय सहायक तहसील कुसमी एवं निर्वाचन सुपरवाईजर के.के. तिवारी निर्वाचन शाखा मझौली की उपस्थिति में बी.एल.ओ. प्रशिक्षण आयोजित किया जाकर निर्वाचन नामावली को त्रुटिरहित बनाने, घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन का कार्य एवं एसआईआर के संबंध में जानकारी दी गई।

सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर हत्या, मारपीट में 3 लोग घायल

सिंगरौली। बारगवां थाना क्षेत्र कसरगाव में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर दो मुस्लिम परिवारों के बीच विवाद हिंसक रूप ले लिया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए। रब्बन निशा के अनुसार, उनके घर के बगल की सरकारी जमीन पर उनका पहले से कब्जा था। स्थानीय निवासी हाजिल का परिवार इस जमीन पर कब्जा करना चाहता था। इसी विवाद में हाजिल और उसके परिवार के करीब 10 लोगों ने लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी और फावड़े से हमला कर दिया।

हमले में रब्बन निशा, उनके पति महताब आलम, पुत्र और देवर शहादत अली घायल हुए। महताब आलम को रीवा के संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। शहादत अली का इलाज सिंगरौली के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। रब्बन निशा और उनके पुत्र की स्थिति सामान्य है। बरगमा थाना प्रभारी ने बताया कि पहले मारपीट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। एक व्यक्ति की मौत के बाद अब धाराएं बढ़ाई जा रही हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए 16 से 31 जुलाई तक अतिरिक्त सीएलसी चरण

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के शासकीय और अनुदान प्राप्त अशासकीय एवं निजी अशासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए यह अतिरिक्त सीएलसी चरण 16 से 31 जुलाई तक आयोजित किया जायेगा। विद्यार्थियों के लिए 16 जुलाई से प्रतिदिन प्रवेश पोर्टल पर महाविद्यालय वार रिक्त सीटों का प्रदर्शन किया जायेगा। विद्यार्थी रिक्त सीटों पर सीधे महाविद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी 16 जुलाई से प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे तक पंजीयन/विकल्प चयन कर सकेंगे। हेल्प सेंटर द्वारा सायं 4 बजे तक प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जायेगा और सायं 5 बजे मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट जारी होने के 24 घंटे के भीतर विद्यार्थियों को प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। प्रवेश शुल्क जमा न किये जाने की स्थिति में प्रवेश मान्य नहीं होगा। विद्यार्थियों को निर्धारित अवधि में प्रवेश शुल्क जमा न करने की दशा में, पुनः रीचॉइस करनी होगी। अतिरिक्त सीएलसी चरण की यह प्रक्रिया 31 जुलाई तक ही होगी।

उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिये एनसीटीई पाठयक्रम (बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एमपीएड, बीएड एमएड (एकीकृत तीन वर्षीय) एवं बी.एल.एड. तथा बी.एड. (अंशकालीन तीन वर्षीय) संचालित करने वाले शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए भी अतिरिक्त चरण की समय सारणी जारी की है। विद्यार्थी 15 से 18 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीयन/आवेदन कर सकेंगे। पंजीकृत आवेदनों के दस्तावेजों का सत्यापन 15 से 19 जुलाई तक होगा। मेरिट सूची का प्रकाशन 21 जुलाई को होगा। विद्यार्थियों के लिए 23 जुलाई को सीट आवंटन किया जाएगा। आवंटित हेल्प सेंटर पर मूल दस्तावेजों, टीसी माइग्रेशन के साथ भौतिक सत्यापन के लिए विद्यार्थियों को उपस्थित होकर 23 से 25 जुलाई तक लिंक इनिशिएट कराना होगा।

विचार

न्याय,जवाबदेही और मानव अधिकारों के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता का प्रतीक है

वैश्विक स्तरपर एक दो दशक से जिस तरह संगठित अपराधोंकी संख्या में अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय व स्थानीय समूह की गतिविधियों में वृद्धि हुई है इसे गंभीरता से रेखांकित करना समय की मांग है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि उनके संगठित अपराधों को अगर हम वर्तमान परिपेक्ष में देखें तो जांचएजेंसियों द्वारा आजकल अपराध की थ्योरी को अन्तर्राष्ट्रीय एंगल से जांच करने की थ्योरी भी अपनाई जाती है जिस तरह से वर्तमान में रूस- यूक्रेन इज़राइल हमास युद्ध,व अनेक देशों के स्थानीय लोकल स्तरोंपर मानवीय अधिकार हनन अपराध चर्चा में आ रहा है व विशेष रूप से युद्ध अपराध चर्चा में आया हैं, युद्ध अपराध के लिए विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय मानक मौजूद हैं, सहित अनेक केसों की तारें विदेशों तक जुड़ी हुई है। एक आपराधिक संगठन को हम गिरोह,माफिया, भीड़, सिंडीकेट, अंडरवर्ल्ड या गैंग्लैंड भी कह सकतें है, जिसमें अनेक अपराध जैसे सफेदपोश अपराध, वित्तीय अपराध, राजनीतिक अपराध, युद्ध के अपराध सहित अनेक परिभाषित अपराधों को शामिल किया जा सकता है जो अंतरराष्ट्रीय कनेक्टेड होते हैं इसीलिए आज हम ऐसे अपराधों और न्याय पर चर्चा करेंगे जो अंतरराष्ट्रीय श्रेणी में आते हैं उनके पीड़ितों को न्याय दिलाने, दुनियाँ भर में हो रहे गंभीर अपराधों पर रोक लगाने विश्व को अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से सचेत रहने के प्रति जागरूक करने के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपलब्ध जानकारी के आधार पर अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई 2025 के उपलक्ष में इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे।

साथियों बात अगर हम आज की दुनिया में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2025 की प्रासंगिकता की करें तो (1) राजनीतिक संघर्षों, युद्ध अपराधों और असंख्य मानवाधिकार उल्लंघनों के इस युग में, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। (2)यह विश्वव्यापी स्तर पर एक पर्याप्त रूप से सुदृढ़ अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था की आवश्यकता की ओर ध्यानआकर्षित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नरसंहार, युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए ज़िम्मेदार, बिना जवाबदेही के न बच सकें।(3) यूक्रेन, गाजा और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में उभर रहे संकटों को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय न्याय एक महत्वपूर्ण तंत्र है जो आम नागरिकों की रक्षा करता है और आगे होने वाले अत्याचारों को प्रभावी रूप से रोक सकता है।(4) यह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) जैसी संस्थाओं और न्याय प्रशासन में राज्यों के बीच सहयोग के महत्व को भी उजागर करता है। (5) ऐसे युग में जहाँ बहुपक्षवाद और कानून के शासन को बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, यह स्मरणोत्सव शांति, जवाबदेही और पीड़ितों के अधिकारों के प्रति वैश्विक निष्ठा की याद दिलाता है। (6) इसलिए यह एक ऐसी न्यायपूर्ण दुनिया की दिशा में प्रेरणा देता है जहाँ न्याय सीमाओं और राजनीतिक हितों से परे जाकरसख्ती से लागू हो।

साथियों बात अगर हम विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाने के उद्देश्यों की करें तो, (1) विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उसे बढ़ावा देना तथा दुनिया में सबसे गंभीर अपराधों के लिए दंड से मुक्ति के विरुद्ध संघर्ष करना है (2) यह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ढ्ढष्टष्ट) जैसे कानूनी तंत्रों के माध्यम से नरसंहार, युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों के कुख्यात अपराधियों को जवाबदेह बनाने की आवश्यकता पर बल देता है। (3) यह दिवस मानवाधिकारों की सुरक्षा, कानून के शासन को बनाए रखने और पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।(4) इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सहयोग और ठोस अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढाँचों के माध्यम से एक अधिक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष विश्व के निर्माण हेतु मिलकर काम करने की याद दिलाता है।

साथियों बात अगर हमअंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) को समझने की करें तो-परिचय (1) यह विश्व का पहला स्थायी, स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है जो उन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है जिन्होंने अत्यंत गंभीर अपराध किए हों।

डॉ. मोहन यादव के दुबई दौरे से खुली मध्यप्रदेश में निवेश की नई राहें

भारत का हृदय प्रदेश मध्यप्रदेश आज मुयमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में औद्योगिक और आर्थिक प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उनके विजन और निवेशकों के प्रति सरकार की पारदर्शी नीतियों ने आज मध्यप्रदेश को देश के सबसे आकर्षक निवेश स्थलों में से एक बना दिया है। हाल के वर्षों में डॉ. यादव की विदेश यात्राओं और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्लेव जैसे नवाचारों ने राज्य में निवेश की लहर को बूस्टर डोज देने का काम किया है।मुयमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश को निवेश के लिए बेहतर स्टेट बनाने के लिए 18 प्रकार की पारदर्शी औद्योगिक नीतियां लागू की हैं। इन नीतियों की बदौलत आज निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम, बिजली बिलों में छूट, और जमीन आवंटन में आसानी जैसे लाभ प्राप्त हो रहे हैं। डॉ. यादव ने निवेशकों को आश्वासन दिया है कि मध्यप्रदेश में निवेश करने पर उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनकी यह प्रतिबद्धता निवेशकों के बीच विश्वास जगाने में सफल रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने बेहद कम समय में निवेश, रोजगार सृजन और शहरी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उनकी पारदर्शी नीतियां, वैश्विक मंचों पर सक्रिय भागीदारी और रोजगार व कौशल विकास पर विशेष जोर ने मध्यप्रदेश को आज भारत का सबसे प्रगतिशील राज्य बना दिया है। निवेश के लिए उनकी लगातार हो रही विदेश यात्राएं अब राज्य की आर्थिक समृद्धि और रोजगार सृजन की दिशा में एक नया अध्याय लिख रही हैं। डॉ. यादव का यह मिशन मध्यप्रदेश को न केवल निवेश का केंद्र बनाएगा, बल्कि इसे धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में भी वैश्विक पहचान मिलेगी । मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने निवेश के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलताएं प्राप्त की हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से लगभग 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा इंग्लैंड, जर्मन और जापान जैसे देशों से 78 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए जो राज्य में 3 लाख से अधिक रोजगार सृजन की संभावना को दर्शाते हैं। इन निवेशों ने मध्यप्रदेश को टेक्सटाइल, रिन्यूएबल एनर्जी, खाद्य प्रसंस्करण, और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अग्रणी बनाने में मदद की है।हाल ही में लुधियाना में उद्योगपतियों के साथ हुए इंटरेक्टिव सेशन में मध्यप्रदेश को 15,606 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए जिससे 20,275 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। जहाँ एक तरफ मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दुबई यात्रा ने देश के हृदयस्थल मध्यप्रदेश को वैश्विक निवेश के मानचित्र पर एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने का कार्य किया है वहीँ दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दुबई दौरे ने मध्यप्रदेश में निवेश, रोजगार सृजन और तकनीकी सहयोग की दृष्टि से नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। यह दौरा आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यटन क्षेत्रों में मध्यप्रदेश की वैश्विक पहचान को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुआ है।डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्यप्रदेश अपनी औद्योगिक और आर्थिक प्रगति के लिए लगातार प्रयासरत रहा है। हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई नीतिगत सुधार किए हैं जिनमें उद्योग-अनुकूल नीतियां, रियायती भूमि आवंटन और पूंजीगत अनुदान जैसे प्रावधान शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ.यादव का दुबई दौरा भारत-यूएई व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने और मध्यप्रदेश को वैश्विक निवेश के लिए एक विश्वसनीय केंद्र के रूप में स्थापित करने में सफल साबित हुआ है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुबई में कई प्रमुख वैश्विक कंपनियों और व्यापारिक संगठनों के साथ उच्च-स्तरीय बैठकें की जिनमें लुलु ग्रुप, सराफ डीजी, ईसा एआई अल गुरैर ग्रुप, गल्फ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स, जी42 इंडिया और टाटा संस मिडिल ईस्ट जैसी कंपनियां शामिल रही। इन बैठकों में स्वास्थ्य, लॉजिस्टिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इन बैठकों में मध्यप्रदेश में निवेश के संभावित क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), लॉजिस्टिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा पर चर्चा हुई। विशेष रूप से धार में पीएम मित्रा पार्क (वस्त्र), तामोट और बिलौआ में प्लास्टिक पार्क, उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क, पीथमपुर में ऑटो, भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक्स, और देवास में फार्मा क्लस्टर जैसे परियोजनाओं को निवेशकों के सामने प्रस्तुत किया गया। गल्फ महाराष्ट्र बिजनेस फोरम और मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम) के साथ हुई चर्चाओं में आपसी सहयोग की नई संभावनाओं पर विचार किया गया। इसके अलावा जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठक में लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया गया।दुबई में आयोजित इन्वेस्ट मध्यप्रदेश दुबई बिजनेस फोरम एंड नेटवर्किंग डिनर इस दौरे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा जहाँ अपनी डिनर डिप्लोमैसी से डॉ. यादव ने निवेशकों को मध्यप्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं और निवेश-अनुकूल नीतियों से अवगत कराया। एमपी की पर्यटन क्षेत्र में जबरदस्त ब्रांडिंग के लिए और भरपूर निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक राउंडटेबल बैठक का आयोजन भी किया गया जहाँ निवेशकों ने मध्यप्रदेश के पर्यटन की प्रशंसा की।

मध्यप्रदेश सरकार ने हाल के वर्षों में निवेश आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। डॉ. यादव ने बताया कि फरवरी 2025 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए जो राज्य की आर्थिक प्रगति का एक मजबूत संकेत है। इसके अलावा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आयोजन से भी निवेश के लिए एमपी की जबरदस्त ब्रांडिंग हुई। दुबई दौरे के दौरान भी निवेशकों ने मध्यप्रदेश में विशेष रूचि दिखाई और कई महत्वपूर्ण निवेश प्रस्ताव सामने आए। दुबई दौरे में शराफ डीजी ग्रुप ने लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए 30-50 मिलियन डॉलर का प्रस्ताव रखा जबकि कोनेरी ग्रुप ने 75 मिलियन डॉलर के स्टील प्लांट की योजना प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त इंदौर इंटरनेशनल बिजनेस नेटवर्क के एक कार्यक्रम में 25 से अधिक कंपनियों के सीईओ की उपस्थिति में सस्टेनेबल सिटी के लिए 1000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया गया। ये निवेश न केवल आर्थिक विकास को गति देंगे, बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेंगे।

दुबई टेक्सटाइल सिटी के दौरे और टेक्समस एसोसिएशन के साथ इंटरएक्टिव सत्र में डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश के वस्त्र उद्योग की क्षमताओं को प्रस्तुत किया। विशेष रूप से धार में पीएम मित्रा पार्क और अन्य टेक्सटाइल क्लस्टरों को बढ़ावा देने की योजनाओं पर जोर दिया गया। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में यूएई की विशेषज्ञता को मध्यप्रदेश की परियोजनाओं के साथ जोड़ने की संभावनाएं तलाशी गई। ग्रू एनर्जी और जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुई चर्चाओं में सतत विकास और पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। डॉ.यादव ने दुबई टेक्सटाइल सिटी में टेक्समस एसोसिएशन परिसर का दौरा किया और वस्त्र उत्पादन तथा निर्यात गतिविधियों का भी अवलोकन किया। इस दौरान एक इंटरएक्टिव सत्र और नेटवर्किंग लंच में मध्यप्रदेश के टेक्सटाइल सेक्टर की क्षमताओं और पीएम मित्रा पार्क जैसी योजनाओं को प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त ग्रू एनर्जी जैसी अग्रणी ग्रीन एनर्जी कंपनी के साथ बैठक में सतत विकास और पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं पर मध्यप्रदेश की प्राथमिकताओं को साझा किया गया।

डॉ. यादव ने यूएई के विदेश व्यापार मामलों के मंत्री डॉ. थानी बिन अहमद अल ज़ियोदी के साथ भी एक महत्वपूर्ण बैठक की जिसमें भारत-यूएई व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत-यूएई सीईपीए (कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमि पार्टनरशिप एग्रीमेंट) के तहत मध्यप्रदेश को निवेश और व्यापार के लिए एक आकर्षक डेस्टिनेशन के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस बैठक में भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत मध्यप्रदेश की भूमिका पर चर्चा हुई। डॉ. यादव ने सौर ऊर्जा, स्मार्ट ऑटोमेशन, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्री 4.0 जैसे क्षेत्रों में यूएई की विशेषज्ञता को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इसके अतिरिक्त, एमिरेट्स एयरलाइंस और दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी के साथ हुई बैठकों में इंदौर और भोपाल से डायरेक्ट फ्लाइट्स और रीजनल कार्गो हब की स्थापना जैसे प्रस्तावों पर सहमति बनी।

संसद का मानसून सत्र इस बार आर या पार

21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है इस बार का मानसून सत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए आर पार की लड़ाई जैसा होगा। केंद्र में गठबंधन की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके पूर्व कभी भी गठबंधन की सरकार नहीं चलाई है। 2002 से लेकर 2024 तक वह हमेशा पूर्ण बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री रहे हैं। 2024 के बाद वह गठबंधन के प्रधानमंत्री हैं। 10 वर्षों के बाद विपक्ष संसद में मजबूत हुआ है। पिछले दो-तीन महीने में जिस तरह की घटनाएं भारत में हुई हैं। उससे सरकार की मुसीबतें बढ़ रही हैं।

पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से केंद्र की सत्ता एका?धिकार के बल पर संचालित हो रही थी। वैसी ही स्थिति 11वें साल में केन्द्र सरकार रखना चा?हती है। जिसके कारण भाजपा की मुसीबतें बढ़ने लगी हैं। केंद्र सरकार में भाजपा के सबसे बड़े सहयोगी राजनीतिक दल तेलुगु देशम पार्टी और बिहार में जनता दल है। यदि इन दोनों दलों द्वारा समर्थन वापस ले लिया जाता है, तो सरकार ?गिर भी सकती है। ऐसी स्थिति में सरकार मध्यावती चुनाव का निर्णय ले सकती है। सदन के अंदर यदि सरकार पराजित होती है, ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन अन्य राजनीतिक दलों के साथ समझौता करके केंद्र में सरकार बना सकती है। यह बात इसलिए लिखना पड़ रही है, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन समीक्षा में जिस तरह की प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा अपनाई जा रही है। उसके कारण चुनाव आयोग की साख पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग की यह पहचान भी बन रही है, वह केंद्र सरकार और भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। चुनाव आयोग मतदाता सूची के लिए जो दस्तावेज मांग रहा है, उसमें आधार कार्ड को मान्य नहीं है। वर्तमान में आधार कार्ड ही भारतीय नागरिकों के पास सबसे प्रमाणिक सरकारी दस्तावेज है। सारे सरकारी कामकाज इसी आधार कार्ड से हो रहे हैं। आधार कार्ड बनाते समय लोगों के आंखों की पुतलियां, फिंगरप्रिंट और उनके परिवार से संबंधित सभी लोगों का आधार कार्ड अ?निवार्य है। चुनाव आयोग आधार के स्थान पर ऐसे दस्तावेज मांग रहा है, जो फर्जी हो सकते हैं। उनकी प्रमाणिकता कभी भी साबित नहीं हो सकती है। इसको लेकर टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट रूप से आयोग के सामने विरोध जता दिया है। जनता दल में मतदाता सूची को लेकर ?बिहार में दो फाड़ हो चुका है। इंडिया गठबंधन पहले ही जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 28 पर्यटकों की मौत, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, जब भारतीय सेना जब पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा रही थी, उस समय सीजफायर करना, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय विमानों का गिरना, भारतीय सेना द्वारा यह कहना कि मीडिया और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण भारतीय सेना को नुकसान हुआ है। पाकिस्तान द्वारा लड़ाई में चीन के हथियारों का इस्तेमाल करने के साथ-साथ चीन द्वारा सैटेलाइट मैपिंग एवं तकनी?कि का भारत के खिलाफ पाकिस्तान को लड़ाई में सहयोग दिया है। ऑपरेशन सिंदूर को दुनिया के किसी देश का समर्थन नहीं मिलने, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का पैकेज मिलने, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने, पाकिस्तान के जनरल मुनीर को अमेरिका बुलाकर व्हाइट हाउस में लंच कराकर सम्मानित करने, चीन के साथ भारत का आयात

और निर्यात घाटा बढ़ने, भारत का चीन के साथ सीमा विवाद, मणिपुर में लगातार अशांति, दलाई लामा को लेकर चीन के साथ तनाव के मुद्दे ?विपक्ष के पास हैं। भारत के उद्योगपति गौतम अडानी, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अब विदेश मंत्री जयशंकर का चीन जाना सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगातार भारत को टैरिफ की धमकी देते हुए अमेरिका से कारोबार बढ़ाने, अमेरिका से कृषि और डेयरी उत्पाद को भारत में आयात करने, रूस के साथ तेल और सैन्य डील को खत्म करने का दबाव बनाया जा रहा है। इन सभी मामलों में सरकार ने चुप्पी साध रखी है। जिसके कारण इस संसद सत्र में सरकार के लिए बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। ?बिहार की मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जजों के खिलाफ महाभियोग को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में तनातनी बनी हुई है। 21 जुलाई से शुरू होने वाले इस मानसून सत्र में सरकार डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक, जीएसटी न्यायाधिकरण विधेयक, सार्वजनिक खरीद विधेयक, दिवालियापन एवं ऋण शोधन संहिता संशोधन विधेयक, खेलों में नैतिक आचरण संशोधन विधेयक, भू वैज्ञानिक विरासत संरक्षण विधेयक, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाए जाने का विधेयक पास कराना चाहती है। इसके अलावा वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। बिहार में सघन मतदाता सूची का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव, चुनाव आयोग मानता है या नहीं, इसको लेकर भी संसद में विपक्ष बहुत आक्रामक भूमिका में होगा। सरकार के सहयोगी दल संसद में कैसा रुख अख्तियार करेंगे, कह पाना मुश्किल है। मानसून सत्र के पहले जिस तरह से सरकार और विपक्ष के बीच में तनाव देखने को मिल रहा है। उससे यह प्रतीत होता है इस बार विपक्ष आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। 1975 में आपातकाल के पूर्व जिस तरह से देश भर में छात्र आंदोलन चल रहे थे। उस समय महंगाई-बेरोजगारी मुख्य मुद्दा था। उस समय राजनीतिक दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफा को राजनीतिक मुद्दा बनाकर आंदोलन को हवा दी थी। इस बार मतदाता अधिकार को लेकर विपक्ष ने मतदाताओं को उद्दे?लित कर ?दिया है। बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों में धुआं उठने लगा है। कब यह ज्वाला में परिवर्तित हो जाएगा कहना मुश्किल है। इस बार विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक मुद्रा में है। ??विपक्ष ?किसी भी स्तर पर जा सकता है। इस बार ?विपक्ष संसद में अपनी ताकत नहीं ?दिखा पाया, तो भविष्य में कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इस स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है।

संसद का मानसून सत्र इस बार सरकार और विपक्ष के लिए आर-पार की लड़ाई जैसा है। ऊंट किस करवट बैठेगा कहना मुश्किल है।

मनेंद्रगढ़ क्षेत्र को मिली 25.99 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात

मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, अधोसंरचना एवं सेंट्रल लाइटिंग मद से स्वीकृत हुए कार्य

स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। शासन की प्राथमिकता में शामिल नगरीय विकास को लेकर मनेंद्रगढ़ क्षेत्र के लिए एक और खुशखबरी सामने आई हैं। मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना, अधोसंरचना मद एवं सेंट्रल लाइटिंग मद अंतर्गत राज्य बजट से मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए कुल 25 करोड़ 99 लाख 82 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चिरमिरी नगर क्षेत्र के लिए 25 करोड़ 99 लाख रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा उपमुख्यमंत्री अरुण साव का आभार व्यक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इन योजनाओं की स्वीकृति से गौरव पथ सड़क, बाईपास सड़क निर्माण, प्रकाश व्यवस्था एवं सेंट्रल लाइब्रेरी जैसे महत्वपूर्ण कार्य अब धरातल पर उतरेंगे, जिससे चिरमिरी के समग्र विकास के संकल्प को नई गति प्राप्त होगी। यह स्वीकृति नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत चिरमिरी नगर पालिका क्षेत्र के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्वीकृत कार्यों में गोदरीपारा से डोमनहिल तक गौरवपथ निर्माण कार्य हेतु 2 करोड़ रुपये, वार्ड क्रमांक 8 बड़ा ग्राउंड से सिद्धबाबा मंदिर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य हेतु 2 करोड़ 40 लाख रुपये, प्रकाश व्यवस्था हेतु 20 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है। इसके साथ ही सांस्कृतिक मंच ग्राम पंचायत से आत्मानंद स्कूल मुख्य मार्ग, चित्ताझोर पोड़ी तक रिटेनिंग वॉल एवं फुटपाथ निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपये, सोनामनी नाका से दीनदयाल चौक पोड़ी तक बायपास कोरिया होते हुए निर्माण हेतु 8 करोड़ 75 लाख 47 हजार रुपये, अन्य अतिरिक्त कार्यों हेतु 6 करोड़ 22 लाख 86 हजार रुपये, तथा सेंट्रल लाइटिंग सह री-डिंग जोन (250 सीटर्स) हेतु 4 करोड़ 41 लाख 49 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस प्रकार कुल मिलाकर चिरमिरी नगर पालिका क्षेत्र को 25.99 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात प्राप्त हुई है, जिससे क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं को मजबूती मिलेगी एवं आमजनो को सुविधाएं प्राप्त होंगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के सतत प्रयासों से यह बड़ी स्वीकृति मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र को प्राप्त हुई है। स्थानीय नागरिकों ने इसके लिए शासन एवं जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया है।

2 दिन से लापता पेंटर की मिली लाश, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

मीडिया ऑडीटर, बिलासपुर (एजेंसी)। 2 दिन से लापता पेंटर की लाश अरपा नदी में मिली है। उसके शरीर पर जख्मों के निशान देखकर परिजन ने हत्या की आशंका जताई है। युवक अपने दोस्त के साथ निकला था, जिसके बाद वो घर नहीं पहुंचा। पुलिस शव का पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। परिजनों के मुताबिक 13 जुलाई को राजू सूर्यवंशी (26) अपने दोस्त कुश कुमार के साथ निकला था। उसने अपने दोस्त के साथ शराब भी पी। जिसके बाद दोनों अपने घरों की ओर निकल गए। लेकिन, राजेंद्र अपने घर नहीं पहुंचा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

नदी में बहता दिखा शवः टीआई विवेक पांडेय ने बताया कि 15 जुलाई को कुछ लोगों ने पचरीघाट के पास नदी में एक युवक का शव अरपा नदी में बहते देखा, जिसके बाद लोगों की भीड़ जुट गई। उन्होंने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर युवक की पहचान नहीं हो पाई। बाद में उसकी पहचान सीपत क्षेत्र के राजेंद्र उर्फ राजू सूर्यवंशी (26) के रूप में हुई।

चिंगराजपारा में रहकर पेंटिंग करता था युवकः पुलिस की पूछताछ में परिजनों ने बताया कि राजेंद्र पोताई और दीवार पर डिजाइन बनाने का काम करता था। वो चिंगराजपारा में रहता था। परिजनों ने यह भी बताया कि वो दो दिन से लापता था, जिसकी तलाश कर रहे थे, उन्होंने कुश कुमार सहित उसके दोस्तों से जानकारी ली। फिर भी उसका कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद उन्होंने सरकंडा थाने में सूचना दी है।

परिजनों ने जताई हत्या की आशंकाः शव का पंचनामा कार्रवाई के दौरान परिजनों ने उसके शरीर पर जख्मों के निशान देखकर हत्या की आशंका जताई है। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि मृतक शराब पीने का आदि था। नदी में गिरने से उसे चोंट लगी होगी। फिर भी मामला संदिग्ध है। पुलिस का यह भी कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही युवक के मौत के कारणों का पता चल सकेगा। जिसके बाद पुलिस आगे की जांच करेगी।

अपर कलेक्टर को सौंपी गई भरतपुर न्यायालय की नई जिम्मेदारी

भरतपुर को मिली नई सौगात अब वहीं होगा न्यायालय और जनदर्शन

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले के विकासखंड भरतपुर के नागरिकों की सुविधा के लिए कलेक्टर डी. राहुल वेंकट द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। उन्होंने नवपदस्थ अपर कलेक्टर विनायक शर्मा को भरतपुर स्थित अपर कलेक्टर न्यायालय की जिम्मेदारी सौंपी है। इस निर्णय से अब भरतपुर ब्लॉक के रहवासियों को न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए जिला मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। वहीं विनायक शर्मा भरतपुर अनुविभाग में नियमित रूप से जनदर्शन के माध्यम से आमजनो की समस्याएं सुनेंगे और त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगे। जनदर्शन प्रत्येक द्वितीय और चतुर्थ मंगलवार को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय, भरतपुर में आयोजित किया जाएगा। इसी दिन अपर कलेक्टर न्यायालय की कार्यवाही दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00

प्रयागराज से लौट रही महिलाओं से मारपीट

कार टक्कर के बाद हुआ था विवाद, आरोपी पकड़ाया

मीडिया ऑडीटर, रायगढ़ (एजेंसी)। जिले में प्रयागराज से लौट रही महिलाओं से मारपीट हुई है। घटना 13 जुलाई की है। जब सिदार परिवार अपने परिवार में बुजुर्ग का अस्थि विसर्जन कर इलाहाबाद से लौट रहा था तभी ग्राम डोलेसरा के पास उनकी फोर व्हीलर को एक कार ने टक्कर मार दी। मामला तमनार थाना क्षेत्र का है। घटना के बाद कार का ड्राइवर सिदार परिवार से गाली-गलौज कर उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा और विवाद के बाद उसने हाथ भी उठाया। आरोपी ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर परिवार की महिलाओं के साथ 7 लोगों को हाथ, मुक्के, डंडे, ईंट और चप्पलों से मारा। इनमें महिलाओं के हाथ में गंभीर चोट भी लगी। पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है और उसके फरार साथियों की तलाश की जा रही है।

यह है मामलाः जानकारी के मुताबिक, लिबरा गांव की रहने वाली कुमारी सिदार (56 साल) अपने ससुर का अस्थि विसर्जन करने अपने परिजनों के साथ इलाहबाद गई थी। वहां से अर्टिगा कार से वे वापस लौट रहे थे और कार को मिनकेतन सिदार चला रहा था। तभी सामने से आ रही स्विफ्ट कार के ड्राइवर प्रकाश पटनायक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। इसके बाद प्रकाश पटनायक ने मौके पर ही ड्राइवर मिनकेतन सिदार के साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट शुरू कर दी।

हाथ-मुक्के डंडे से पीटा थाः ऐसे में कार सवार कुमारी सिदार, रतन कुंवर, बूंदकुंवर, पुनी बाई, नेहरू सिदार और नारदी सिदार बीच-बचाव के लिए आए तो प्रकाश फोनकर अपने साथी वरुण सिदार और अन्य लोगों को बुला लिया। मौके पर पहुंचे प्रकाश और उसके साथियों ने परिवार की महिलाओं और अन्य के साथ हाथ, मुक्के, डंडे, ईंट और चप्पलों से मारपीट की। इससे उन्हें गंभीर चोट पहुंची।

घटना के बाद आरोपी फरार हुएः घटना को देखकर आसपास के लोगों ने बीच-बचाव किया। जिसके बाद कुमारी सिदार ने थाना पहुंचकर मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई। जहां पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले में जांच शुरू की, लेकिन घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए थे।

मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कियाः मंगलवार 15 जुलाई को तमनार टीआई कमला पुसाम ठाकुर को सूचना मिली कि आरोपी प्रकाश पटनायक घरघोड़ा की ओर छिपा है। जिसके बाद पुलिस ने उसकी खोजबीन शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसके अन्य साथी फरार हैं। जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

पति-पत्नी का मर्डर, घर के अंदर मिली लाश; शरीर पर चोट के निशान

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (एजेंसी)। अभनपुर में एक घर के अंदर पति-पत्नी की लाश मिली है। किसी ने धारदार हथियार से दोनों की हत्या की है। शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। इस मामले में एफएसएल, क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुटी है। मामला अभनपुर थाना क्षेत्र के बिरोदा गांव का है।

पुलिस के मुताबिक, बुधवार सुबह पुलिस को सूचना मिली के बिरोदा गांव में रहने वाले भूखन ध्रुव (62) और उनकी पत्नी रुक्मणी ध्रुव (60) की घर पर लाश पड़ी है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, तो घर के एक कमरे में पलंग पर भूखन की लाश पड़ी थी। पत्नी रुक्मणी की लाश दूसरे कमरे में जमीन पर पड़ी थी।

लाश के आसपास खून बिखराः घटनास्थल पर एसीसी टीम, एफएसएल यूनिट, फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट, डॉग स्क्वॉड जांच में जुटी हैं। लाश के आसपास खून बिखरा हुआ है। पुलिस को शक है कि यह वारदात किसी करीबी ने की है। हत्या के लिए किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया है। दोनों मृतकों के शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं। घर के भीतर कई सामान बिखरा हुआ है। फिलहाल पंचनामा के बाद लाश को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा जा रहा है।

दंपती के हैं तीन बच्चेः पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, भूखन और उसकी पत्नी खेती किसानी करते हैं। भूखन एक दूसरे व्यक्ति के खेत में कीटनाशक छिड़कने का काम कर रहा था। बुधवार को काम पर नहीं पहुंचा तो वह व्यक्ति उसे घर पर देखने आया था, तभी उसने लाश देखकर उसने सरपंच को सूचना दी। इसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा। बताया जा रहा है कि भूखन के तीन बच्चे हैं। जिसमें दो लड़की और एक लड़का है। लड़कियों की शादी धमतरी और पाटन में हुई है। वहीं लड़का रायपुर में रहता है। फिलहाल, पुलिस परिवार के सदस्यों को भी बुलाकर पूछताछ कर रही है।

बीमार बेटे को ठीक करने मासूम की चढ़ाई बलि

छुरी से 3 साल के बच्चे का गला काटा, नाले के पास दफनाया सिर-धड़

मीडिया ऑडीटर, बलरामपुर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में अपने मानसिक रूप से बीमार बेटे के इलाज के लिए पिता ने 3 साल के मासूम की बलि चढ़ा दी। मिठाई-बिस्कुट खिलाने के लिए जंगल से बच्चे को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। फिर पूजा पाठ कर लोहे की छुरी से मासूम का गला काट दिया। इस बीच सवा साल बाद आरोपी राजू कोरवा (40) ने गांव में ही किसी को बता दिया कि, उसने बड़ा पूजा की है। शक के आधार पर जब पुलिस ने उसे पकड़ा, तो अपना जुर्म कबूल कर बताया कि, उसने अंधविश्वास के चलते यह हत्या की है। मामला सामरी थाना क्षेत्र के सुलुगडीह का है।

यह है मामलाः दरअसल, सुलुगडीह निवासी रसोईया बिरेंद्र नगेशिया (24) अपनी पत्नी दयामुनि के साथ इलबासा जंगल में झोपड़ी बनाकर 29 मार्च 2024 से महुआ बीनने का काम कर रहा था। इस बीच उनका 3 साल का बेटा अजय नगेशिया 1 अप्रैल 2024 को जंगल से लापता हो गया। 6 अप्रैल को उसने बच्चे के गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई।

सवा साल बाद पुलिस को मिला सुरागः बलरामपुर एसपी वैभव बैंकर ने बताया कि, गुमशुदगी के बाद लगातार खोजबीन की जा रही थी। इस बीच मृतक के दादा और एक सहयोगी को सूचना मिली कि, राजू कोरवा 'बड़ा पूजा' की बात कर रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने राजू कोरवा को हिरासत में लिया। पहले तो उसने नशे में बात कहना बताकर टालने की कोशिश की, लेकिन सख्ती से पूछताछ में उसने पूरी घटना स्वीकार कर ली।

बेटे को ठीक करने की लालसा में दी बलिः पूछताछ में राजू कोरवा ने बताया कि, उसका बड़ा बेटा बचपन से मानसिक रूप से कमजोर है। उसे मिर्गी की बीमारी है। किसी ने उससे कहा था "महादानी देवता" को बच्चे की बलि देने से वह ठीक हो जाएगा। अंधविश्वास के चलते इस सोच ने उसे हैवान बना दिया। 1 अप्रैल 2024 को राजू कोरवा इलबासा के जंगल में गया था, जहां उसे अजय नगेशिया अकेले घूमते मिला। राजू कोरवा उसे मिठाई और बिस्कुट देने का लालच देकर अपने घर कटईडीह ले आया। उसने घर में "महादानी देवता" की पूजा की और अजय की गला काट काटकर उसकी बलि चढ़ा दी।

ग्राम श्रीपुर में हैंडपंप मरम्मत और क्लोरीनेशन से ग्रामीणों को मिला स्वच्छ पेयजल

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले के मनेन्द्रगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत केवटी के ग्राम श्रीपुर में स्वच्छ पेयजल की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा यहां वर्षों से उपयोग में आ रहे हैंडपंप की मरम्मत की गई, साथ ही जल स्रोत की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए क्लोरीनेशन का कार्य भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पिछले कुछ समय से हैंडपंप से गंदे पानी की शिकायतें मिल रही थीं, जिससे ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं सताने लगी थीं। विभाग की तकनीकी टीम ने मौके पर पहुंचकर हैंडपंप की मरम्मत की और जल में क्लोरीन मिलाकर उसे कीटाणुरहित किया गया। इस कार्य के बाद ग्रामीणों को साफ, सुरक्षित और पीने योग्य पानी उपलब्ध होने लगा है। कार्यक्रम के दौरान ग्रामवासियों ने सक्रिय सहयोग और उपस्थिति दर्ज कराई। स्थानीय लोगों ने विभाग के इस प्रयास की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह पहल न केवल उनके स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाएगी, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सकारात्मक बदलाव लाएगी। विभागीय अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया कि स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कार्य आगे भी समय-समय पर होते रहेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल जनित बीमारियों को रोका जा सके।

दिव्यांगों को घसीटकर ले गई पुलिस, विधानसभा घेरने की तैयारी में संघ

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (एजेंसी)। बस स्टैंड के पास बैठे दिव्यांग संघ के लोगों को पुलिस ने बलपूर्वक उठाया और गाड़ी में डालकर नवा रायपुर स्थित तूता धरनास्थल ले गई। इसका वीडियो भी सामने आया है। जिसमें पुलिस महिलाओं और पुरुषों को घसीटकर हटाते नजर आ रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी करने वाले 148 अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग को लेकर आज प्रदेश के सभी दिव्यांग संघ विधानसभा घेराव करने वाले हैं।

महिला दिव्यांगों के साथ बदसलूकी का आरोपः विधानसभा घेराव से पहले वायरल हुए वीडियो में पुलिस महिला दिव्यांगों को घसीटते और बदसलूकी करते दिख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर निकले थे, लेकिन पुलिस उन्हें प्रदर्शन करने से रोक रही है। दिव्यांग संघ के लोगों ने बताया कि इससे पहले भी कई बार प्रदर्शन किया है और सरकार के आश्वासन के बाद उन्होंने अपना आंदोलन वापस लिया। लेकिन अब तक मांगे पूरी नहीं होने पर आज सभी दिव्यांग विधानसभा का घेराव करने रायपुर पहुंच रहे हैं।

पत्नी का कॉल डिटेल- सीडीआर मांगना निजता का हनन

हाईकोर्ट ने कहा- गोपनीयता संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है, पति की याचिका खारिज

मीडिया ऑडीटर, बिलासपुर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि गोपनीयता संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है, जो मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी से देता है। इस टिप्पणी के साथ ही जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने विवाद होने पर पति के पत्नी की मोबाइल कॉल डिटेल और सीडीआर की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दी है।

दरअसल, याचिकाकर्ता दुर्ग जिले के युवक की शादी राजनांदगांव जिले के युवती से 4 जुलाई 2022 को हिंदू रीति-रिवाज के साथ हुई थी। विवाह के कुछ समय बाद ही पति ने डिवोर्स के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1) (1) के तहत एक याचिका दायर की। इसमें आरोप लगाया गया कि पत्नी विवाह के 15 दिन बाद अपने माता-पिता के घर गई, जिसके बाद उसका व्यवहार काफी बदल गया।

आरोप है कि पत्नी ने याचिकाकर्ता की मां और भाई के साथ दुर्व्यवहार किया। इस बीच सितंबर और अक्टूबर के महीने में पत्नी फिर से अपने माता-पिता के घर गई और जब याचिकाकर्ता ने उससे संपर्क किया, तो उसने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। पत्नी के साथ न जाने पर पति 7 अक्टूबर 2022 को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए फैमिली कोर्ट में केस दाखिल किया।

पति ने पुलिस से मांगी पत्नी का मोबाइल कॉल डिटेलः इस दौरान पत्नी ने धारा 125 के तहत एक आवेदन पेश किया। साथ ही पति की मां, पिता और भाई के खिलाफ घरेलू हिंसा के तहत शिकायत की। इस पर पति ने 24 जनवरी 2024 को दुर्ग के एसएसपी को आवेदन देकर पत्नी की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की डिटेल की मांग की। लेकिन, पुलिस ने कॉल डिटेल देने से इनकार कर दिया। इस पर पति ने कॉल डिटेल के लिए फैमिली कोर्ट में आवेदन दिया, जिसे खारिज कर दी गई। इसके बाद वह हाईकोर्ट पहुंचा।

हाईकोर्ट बोला- यह निजता के अधिकार का उल्लंघन हैः अपनी याचिका में पति ने पत्नी की चरित्र पर लांछन लगाते हुए मोबाइल पर दूसरे से बातचीत करने के सबूत होने का दावा किया। जिसके लिए उसने कॉल डिटेल की मांग की। लेकिन, फैमिली कोर्ट में दाखिल किए गए केस में पति ने तलाक के लिए लगाई गई अर्जी में उल्लेख ही नहीं किया। उन्होंने पत्नी के व्यवहार में बदलाव और साथ रहने से इनकार करने का जिक्र किया है। सुनवाई के दौरान पत्नी की ओर से कहा गया कि वैवाहिक जीवन साझेदारी का संबंध होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी की व्यक्तिगत गोपनीयता खत्म हो जाती है। पति पत्नी को अपने मोबाइल या बैंक पासवर्ड देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता और ऐसा करना गोपनीयता का हनन और घरेलू हिंसा माना जा सकता है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने कहा कि पति ने अपनी तलाक की अर्जी में कहीं भी चरित्रहीनता का आरोप नहीं लगाया है। ऐसे आरोप लिखित बहस में पहली बार लगाए गए हैं। इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जिसमें गोपनीयता भी शामिल है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए पति की याचिका को खारिज कर दिया।

जेल से छूटकर 70 साल की बुजुर्ग से किया रेप

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बेटा 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ 4-5 दिनों तक रेप करता रहा। जब वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो वृद्ध ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। इससे पहले वो 5 साल की बच्ची से भी दुष्कर्म कर चुका है। घटना मामला आरंग थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी 42 साल का है। जेल से छूटने के बाद वो बुजुर्ग महिला से छेड़खानी करने लगा। उसने इसका विरोध किया, लेकिन वो नहीं माना। उसने कुछ दिन पहले ही चार से पांच दिनों तक लगातार रेप किया। 15 जुलाई को पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत की।

5 साल की बच्ची से भी किया था रेपः इसी आरोपी ने साल 2010 में 5 साल की बच्ची से रेप की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। लेकिन 2017 में आरोपी जेल से छूटकर बाहर आ गया। इसके बाद उसने अपनी बुजुर्ग महिला के साथ छेड़छाड़ भी किया था। इस संबंध में भी उसने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी।

2.11 लाख बच्चों की स्क्रीनिंग होगी, दस्तक अभियान 22 से शुरू होगा, टास्क फोर्स की बैठक

भिंड (एजेंसी)। जिले में बाल स्वास्थ्य और पोषण सुधार के लिए 22 जुलाई से 16 सितम्बर तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागृह में जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक हुई। इसमें में अभियान की तैयारियों और विभागीय जिम्मेदारियों पर चर्चा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए।

उन्होंने कहा अभियान के हर चरण की सघन मॉनिटरिंग हो और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को तत्काल पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया जाए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे.एस. यादव ने बताया कि दस्तक अभियान का आयोजन 22 जुलाई से 16 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। इसमें जिले भर के लगभग 2 लाख 11 हजार बच्चों की जांच की जाएगी।

गुना के पारदी गिरोह ने गुजरात में की डकैती, 6 आरोपी गिरफ्तार

गुना (एजेंसी)। अहमदाबाद में हुई तीन बड़ी चोरियों का खुलासा करते हुए गुजरात पुलिस ने मध्यप्रदेश के गुना जिले के रहने वाले पारदी गिरोह के छह बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 12 लाख रुपए की घड़ी, 1.50 लाख रुपए नकद और चोरी में उपयोग किए जाने वाले औजार बरामद किए गए हैं। अहमदाबाद के सोला हाईकोर्ट और नरोड़ा थाना क्षेत्र में पिछले डेढ़ महीने में घरों में चोरी की तीन वारदातें हुई थीं। आरोपियों ने हाइड्रोलिक कटर से खिड़की की सलाखें काटकर घरों में घुसपैठ की और नकदी, जेवर और महंगी घड़ियां चुरा ली थीं।

बिजली चोरी पकड़ने गए अधिकारी से मारपीट

सीहोर (एजेंसी)। जिले में बिजली कंपनी के जोन-1 में अधिकारी के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। कस्बा क्षेत्र में बिजली चोरी की जांच के दौरान असिस्टेंट इंजीनियर अतुलेश के साथ दुर्व्यवहार किया गया।

बुधवार को एई अतुलेश अपनी टीम के साथ इलाके में बिजली चोरी पकड़ने का अभियान चला रहे थे। उन्होंने एक जगह डायरेक्ट लाइन से बिजली चोरी पकड़ी। बिजली की तार में कट लगाकर अवैध रूप से बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था।

सीए ने राजनीतिक पार्टी को 2 करोड़ का दिलाया चंदा

4 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी करवाई; इंदौर में कमीशन के बदले काम किया

इंदौर (एजेंसी)। आयकर विभाग की टीम ने सोमवार-मंगलवार को देशभर में कार्रवाई की। इंदौर में यह कार्रवाई सीए शुभम लड्ढा और एक कर सलाहकार प्रकाश जैन के घर व ऑफिस पर की गई। सूत्रों के अनुसार इस कार्रवाई के दौरान पता चला है कि सीए और कर सलाहकारों ने रिपब्लिकन बहुजन समाज पार्टी को डेढ़ से दो करोड़ का चंदा दिलवाया है। मप्र निर्वाचन आयोग के अनुसार मप्र में 106 राजनीति दल सक्रिय हैं। इनमें 5 राष्ट्रीय पार्टी हैं। छह राज्यस्तरीय दल हैं। वहीं, पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या 95 है। इसमें इंदौर में रिपब्लिकन बहुजन पार्टी का नाम सामने आया है, जिसे सीए शुभम लड्ढा ने तकरीबन 70 लोगों से चंदा दिलवाया है। ये चंदा 1 से 5 लाख के बीच है।

हालांकि, शुभम ने दो-तीन साल पहले ही काम शुरू किया है। बताया जा रहा है कि इसका बड़ा खिलाड़ी प्रकाश जैन है, जिसका ऑफिस 60 फीट रोड छोटा बांगड़दा पर है। वह काफी लम्बे समय से काम कर रहा है। सूत्रों की मानें तो यहां भी शुरूआती दौर में संदिग्ध दान के 50 से अधिक मामले मिले हैं। कार्रवाई के दौरान आम भारतीय पार्टी, स्वर्णिम भारत, भारतीय क्रांति संघ, राष्ट्र वाहिनी पार्टी, इंपीरियल

पार्टी ऑफ इंडिया, एकता निर्माण नेशनल पार्टी और मालवा कांग्रेस का नाम सामने आया है।

छापे में इंदौर, रतलाम के यह लोग धराए: आईटी के जरिए फर्जी रिफंड मामले में की गई छापामार कार्रवाई में इंदौर के सीए शुभम लड्ढा के यहां जांच हुई है। इसमें उनके सहयोगी निखिल मंत्री और अन्य से भी पूछताछ हुई। वहीं, एरोड्रम एरिया में रहने वाले कर सलाहकार प्रकाश जैन के यहां भी टीम पहुंची थी और जांच की गई। रतलाम में कर सलाहकार सुरेश गुप्ता के भी यहां जांच हुई है। उज्जैन में एजेंट सत्येंद्र टूटेजा और संजय चौधरी के यहां भी कार्रवाई हुई।

लड्ढा ने 4 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी करवाई: आयकर जांच में आया है कि सीए, कर सलाहकार और मध्यस्थों के गठबंधन ने फर्जी रसीद, राजनीतिक चंदे, मेडिकल के फर्जी बिल, ट्यूशन फीस आदि की रसीदें बताकर करदाता को टैक्स रिफंड दिलवाया। साथ ही इसके बदले में जमकर कमीशनखोरी की है। लड्ढा के ठिकानों पर जांच में करीब चार से पांच करोड़ की फर्जी इनकमटैक्स छूट, रिफंड का मामला सामने आया है। उनके जरिए कई बड़े वेतन वाले कर्मचारियों के रिटर्न भरे जा रहे थे। रतलाम के सुरेश गुप्ता के यहां भी कैश, ज्वैलरी मिली है।

5 महीने पहले देवास के सीए जैन से खुली फाइल: फर्जी रिफंड की फाइल खुलने की बात भी इंदौर, उज्जैन इनकम टैक्स रीजन से ही सामने आई। इस रीजन में इनकम टैक्स अधिकारियों के संज्ञान में मामला आया कि यहां पर टैक्स जमा के अनुपात में टैक्स रिफंड तेजी से बढ़ा है। खासकर टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोस) भरने में भारी फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसके जरिए बड़ा वेतन पाने वाले और कमाई करने वाले रिफंड ले रहे हैं। इसमें जब जानकारी जुटाई गई तो सीए नीरज जैन जो देवास में काम करते हैं और उज्जैन सीए ब्रांच में रजिस्टर्ड हैं। उनके एक ही आईपी एड्रेस से कई ईमेल के जरिए टैक्स रिटर्न भरने और रिफंड क्लेम करने की जानकारी सामने आई।

40 हजार करदाताओं ने आइटी रिटर्न में किया संशोधन: 2.29 लाख कर्मचारी, 7124 करोड़ का फर्जी क्लैम मुंबई, पुणे और नागपुर क्षेत्र में कुल 86058 कर्मचारियों ने 2488 करोड़ की कटौती का दावा किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र (एनडब्ल्यूआर) क्षेत्र में 47571 कर्मचारियों ने 1382 करोड़ की कटौती का दावा किया। प. बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर पूर्व के संयुक्त क्षेत्र में 8597 कर्मचारियों ने 223 करोड़ की कटौती का दावा किया है। कर्नाटक, गोवा, आंध्र, तेलंगाना में 49,580 कर्मचारियों ने 1641 करोड़ का दावा किया। राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में 37,822 कर्मचारियों ने कुल 1117.93 करोड़ का दावा किया। आयकर विभाग द्वारा फर्जी कटौती और छूट पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई के बाद पिछले 4 महीनों में 40,000 करदाताओं ने आयकर रिटर्न में संशोधन किया और 1,045 करोड़ के धोखाधड़ी वाले दावों को वापस लिया। इस बात की जानकारी आयकर विभाग ने 14 जुलाई को अपनी प्रेस रिलीज में दी।

वाटरफॉल में शराब पी, 3 दिन बाद वहीं उठक-बैठक लगाई

युवकों ने कान पकड़कर माफी मांगी; बोले- दोबारा ऐसा नहीं करेंगे

शिवपुरी (एजेंसी)। रविवार को झरने के नीचे बैठकर कुछ युवकों ने पहले शराब पार्टी की। इसके बाद स्थानीय लोगों की नाराजगी के बाद वहीं पर आकर उठक-बैठक लगाई और माफी मांगी। युवकों ने शर्मिंदगी जताते हुए दोबारा ऐसा नहीं करने की बात कही। इसके दोनों ही वीडियो सामने आए हैं। मामला भौंती थाना क्षेत्र के चौकी खोड़ के ग्राम बीरा स्थित सिद्ध क्षेत्र केरखो धाम का है। तीन दिन पहले इस पवित्र स्थल के झरने के नीचे शराब पार्टी का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो में कुछ युवक झरने के नीचे बैठकर शराब

पीते नजर आए।

वीडियो में बीरा गांव के रघुवीर पुत्र बिस्सी जाटव, अमित पुत्र मुकेश जाटव, राजकुमार पुत्र लल्लू जाटव सहित अन्य युवक शराब के पैग टकराते दिखाई दिए। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्रीय लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और उनमें आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने युवकों की इस हरकत पर नाराजगी जताई।

विरोध के बाद युवकों ने मांगी माफी: युवकों की हरकत पर स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन से शिकायत कर सख्त कार्रवाई की मांग की। विरोध बढ़ता देख सभी युवक बुधवार (16 जुलाई) को फिर धार्मिक स्थल केरखो धाम पहुंचे। उसी जगह पर कान पकड़कर उठक-बैठक लगाई और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। युवकों ने अपने किए पर शर्मिंदगी जताते हुए दोबारा ऐसा नहीं करने की बात कही।

डिलीवरी से पहले जुड़वां बच्चों की मौत

परिजनों का आरोप- डॉक्टर ने लापरवाही बरती, डिलीवरी से पहले 25 हजार रुपए मांगे

छतरपुर (एजेंसी)। एक निजी अस्पताल में प्रसव से पहले पेट में पल रहे जुड़वां बच्चों की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि गर्भावस्था के दौरान लगातार इलाज कराने के बावजूद डॉक्टरों ने प्रसव के समय लापरवाही बरती। साथ ही अस्पताल प्रशासन पर मनमाने तरीके से पैसे वसूलने के भी आरोप लगाए गए हैं। बजरंग नगर निवासी जितेंद्र यादव ने बताया कि उनकी पत्नी का इलाज 9 महीने से मिशन अस्पताल की डॉ. रूपा मैडम के पास चल रहा था। 13 जुलाई को पेट में दर्द हुआ तो रात में भर्ती कराया गया, लेकिन सुबह छुट्टी दे दी गई। डॉक्टर ने कहा कि डिलीवरी का समय आ गया है। 15 जुलाई को फिर अस्पताल लाए, जहां रात में दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया। जितेंद्र का कहना है कि

इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी, सारी जांच और दवाएं समय पर लीं, फिर भी लापरवाही से ये स्थिति बनी।

फीस को लेकर भी नाराजगी: परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने एक रात के 10,000 लिए और डिलीवरी से पहले 25,000 और मांगे। इलाज के दौरान डॉक्टर समय पर नहीं आईं और फोन पर बताया गया कि वे किसी अन्य काम में व्यस्त हैं।

सीएमएचओ बोले- शिकायत मिली तो कार्रवाई होगी: इस मामले में सीएमएचओ डॉ. आरपी गुप्ता ने कहा कि यदि इस मामले में शिकायत मिलती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

छत रिपेयर करते गिरे मजदूर, एक आईसीयू में भर्ती

एंगल पर लटके साथी को बचाया, खुद पहले गिरा; चद्दर धंसने से हादसा

खंडवा (एजेंसी)। दो मजदूर टीनशेड सुधारते समय गिर गए। एक की हालत ज्यादा गंभीर है, उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है। हादसा नर्मदानगर स्थित आईटीआई कॉलेज की छत रिपेयरिंग के दौरान मंगलवार को हुआ। इसका वीडियो बुधवार को सामने आया है।

निजी कंपनी के दो मजदूर पुरानी हो चुकी सीमेंट की शीट बदलकर टीन शेड डाल रहे थे। इसी दौरान एक मजदूर गिरते हुए लोहे के एंगल पर लटक गया। उसे बचाने के लिए दूसरे मजदूर ने बेल्ट दिया, ताकी वो उसे बांधकर नीचे आ सके। मजदूर जैसे ही नीचे उतरने लगा, लोड बढ़ने के कारण सीमेंट की शीट टूट गई। ऊपर से बेल्ट देने वाला मजदूर भी नीचे गिर गया। उसकी हालत गंभीर हैं।

पुरानी शीट हटाते समय हादसा: छत पर पुरानी शीट लगी

थीं, जो कमजोर हो गई थी। उन्हें बदलकर लोहे के टीन लगाए जाने हैं। इस काम के लिए मजदूरों को लगाया हैं, दो मजदूर छत पर चढ़कर काम कर रहे थे। इनमें बीनू दरबार और अन्नू जया थे, पुरानी शीट पर चढ़कर उन्हें निकाल रहे थे कि एक मजदूर बीनू दरबार गिरने लगा। गनीमत रही कि वह लोहे की एंगल पर लटक गया फिर उसे बचाने के लिए ऊपर मौजूद अन्नू जया ने सपोर्ट के लिए बेल्ट दिया। बेल्ट बांधकर दरबार नीचे उतरने लगा कि छत पर अचानक खिंचाव हुआ और चद्दर धंसने से जोया भी नीचे गिर गया।

घटनाक्रम के दौरान वहां मौजूद एक मजदूर वीडियो बना रहा था। दो मजदूरों के गिरने के बाद अफरा-तफरी मच गई। बाकी मजदूर पहुंचे और उन्हें संभाला। इनमें बीनू दरबार को खरोंच तक नहीं आई। वहीं बीनू की मदद करने वाले जोया को गंभीर चोंट आई हैं। परिवार वाले इलाज के लिए इंदौर लेकर गए हैं। जहां अन्नू जोया को एक निजी अस्पताल के आईसीयू भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक, हालत काफी क्रिटिकल हैं।

रेप का आरोप लगा तो ट्रेन के सामने कूदा

शव रखकर चक्काजाम, पथराव; पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, लाठीचार्ज किया

दतिया (एजेंसी)। ग्वालियर के डबरा में एक युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर सुसाइड कर लिया। उस पर कुछ घंटे पहले ही रेप का केस दर्ज हुआ था। गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे- 44 के बड़ोंकलां तिराहे पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शन के दौरान हालात बेकाबू हो गए, लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने भीड़ काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। घटना मंगलवार की है। गोराघाट के ग्राम पचोखरा के रहने वाले 21 साल के आकाश रावत पर दोपहर करीब 2.30 बजे एक युवती ने गोराघाट थाने में रेप का केस दर्ज कराया। पुलिस आकाश को पकड़ने डबरा पहुंची, लेकिन वह फरार हो गया। कुछ ही देर बाद उसने सिमरिया टेकरी के पास ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी।

मौत से पहले परिजन को कॉल किया: परिजनों के अनुसार, सुसाइड से पहले आकाश ने

अपने ताऊ महेंद्र सिंह रावत को कॉल किया था। उसने कहा था- 'पुलिस पीछा कर रही है, मैं रेलवे ट्रैक की तरफ भाग रहा हूं।' परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आकाश की मौत हो चुकी थी।

युवती के परिजन कर रहे थे पैसों की मांग: आकाश के ताऊ महेंद्र सिंह रावत ने बताया, रविवार को गांव की युवती घर से चली गई थी। उसके परिजन ने आकाश पर उसे भगाने का आरोप लगाकर गोराघाट थाने में शिकायत की थी। सोमवार को थाने में दोनों पक्षों को बुलाया गया और समझौते की कोशिश की गई। युवती के परिजन ने समझौते के एवज में 15 से 20 लाख रुपए की मांग की। आकाश के परिवार ने 10 लाख रुपए देने की बात कही, लेकिन सहमति नहीं बनी। इसके बाद एफआईआर दर्ज कर दी गई। इसके बाद आकाश मानसिक तनाव में आ गया। मंगलवार को उसने सुसाइड कर लिया।

शव रखकर चक्काजाम, पुलिस पर पथराव: मंगलवार देर रात परिजन आकाश का शव लेकर नेशनल हाईवे पहुंचे और बड़ोंकलां तिराहे पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। करीब ढाई घंटे तक हाईवे पर पांच किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने जब जाम खोलने की कोशिश की तो स्थिति बिगड़ गई। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे पुलिस के वाहन और कुछ राहगीरों की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।

उपद्रव में 11 नामजद और 45 अज्ञात पर केस: एसपी सूरज कुमार वर्मा ने बताया, प्रदर्शन के दौरान सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचा और पुलिस पर हमला किया गया। इस मामले में गोराघाट थाना पुलिस ने 11 नामजद और 40-45 अज्ञात लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, पथराव, और राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध करने सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।

एमपी के पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता प्रक्रिया पर रोक

हाईकोर्ट ने दिया आदेश, बैकडेट में दी जा रही थी 2023 सत्र की मान्यता

जबलपुर (एजेंसी)। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता को लेकर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने उन कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, जो बिना नियमों के मान्यता दे रहे थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मध्यप्रदेश में जितने भी पैरामेडिकल कॉलेज हैं, उनकी मान्यता प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाई जाती है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि कॉलेजों को सत्र 2023 की मान्यता बैकडेट में दी जा रही थी। इसके अलावा, मेडिकल यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट के बिना ही छात्रों को दाखिले दिए जा रहे थे।

नर्सिंग की तरह पैरामेडिकल कोर्स में भी फर्जीवाड़ा: इस मामले की सुनवाई नर्सिंग घोटाले से जुड़ी जनहित याचिका के दौरान हुई। लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में एक अतिरिक्त आवेदन पेश किया, जिसमें बताया गया कि नर्सिंग की तरह ही पैरामेडिकल कोर्स में भी

बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। आवेदन में बताया गया कि एमपी पैरामेडिकल काउंसिल ने 2023-24 और 2024-25 सत्र की मान्यता बिना किसी जांच या निरीक्षण के बांट दी।

बिना संबद्धता के अवैध दाखिले, सीबीआई की रिपोर्ट को भी किया नजरअंदाज: यह भी आरोप लगाया गया कि कई सरकारी और निजी पैरामेडिकल कॉलेज बिना यूनिवर्सिटी की संबद्धता के अवैध रूप से छात्रों को एडमिशन दे रहे हैं। जिन कॉलेजों को नर्सिंग घोटाले की जांच में सीबीआई ने "अनसूटेबल" बताया था, उन्हीं इमारतों में अब पैरामेडिकल कॉलेज चलाए जा रहे हैं और उन्हें मान्यता दी जा रही है।

नई जनहित याचिका दर्ज करने के निर्देश दिए थे: हाईकोर्ट ने इस गंभीर मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए शुक्रवार को निर्देश दिए थे कि याचिकाकर्ता का नया आवेदन अलग जनहित याचिका के रूप में पंजीबद्ध किया जाए। साथ ही, मध्यप्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल के चेयरमैन और रजिस्ट्रार को भी इस मामले में पक्षकार बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

अगली सुनवाई 24 जुलाई को: हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश के पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता और एडमिशन प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई की तारीख 24 जुलाई तय की है। इस दिन सभी नर्सिंग घोटालों से जुड़ी याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। बता दें, मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ. राजेंद्र शुक्ला पैरामेडिकल काउंसिल के पदेन चेयरमैन हैं।

उल्टी-दस्त से पीड़ित बच्चे को एक्सपायरी डेट की ड्रिप चढ़ाई

डॉ. राजेंद्र तिवारी ने कहा-जांच के बाद दोषियों पर होगी कार्रवाई

पन्ना (एजेंसी)। जिला अस्पताल में एक लापरवाही का मामला सामने आया है। मंगलवार रात यूसुफ बेग ने अपने 11 साल बेटे जीशान को उल्टी-दस्त की शिकायत पर बच्चा वार्ड में भर्ती कराया।

नर्स ने एक्सपायरी डेट की बोतल चढ़ाई: बुधवार को डॉक्टर के राउंड के बाद नर्स ने बच्चे को एक बोतल चढ़ाई। कुछ समय बाद बच्चे को तेज ठंड लगने लगी और उसकी हालत बिगड़ने लगी। परिजनों ने तुरंत नर्स को बुलाया। जांच में पता चला कि बोतल की एक्सपायरी डेट मार्च 2025 थी।

बच्चे के पिता यूसुफ बेग ने कहा कि समय पर ध्यान देने से बड़ी घटना टल गई। हमने अस्पताल प्रबंधन से शिकायत की है। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र तिवारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच टीम का गठन किया है।

उन्होंने कहा कि जांच के बाद दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

संक्षिप्त समाचार

टेस्ला की भारत में पहली कार लॉन्च

मुंबई (एजेंसी)। इलॉन मस्क की ईवी कंपनी टेस्ला ने पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी मॉडल वाय को भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि ये कार एक बार फुल चार्ज में 622 किलोमीटर तक चल सकती है। कार में सेफ्टी के लिए 8 एयरबैग के साथ लेवल-2 एडास जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक कार को भारत में दो वैरिएंट- रियर व्हील ड्राइव (आरडब्ल्यूडी) और लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव (आरडब्ल्यूडी) में पेश किया गया है। इसकी आरडब्ल्यूडी वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 60 लाख रुपए है। वहीं लॉन्ग रेंज वैरिएंट की कीमत 68 लाख रुपए है। जबकि, ग्लोबल मार्केट में ये कार ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ भी आती है। कार की बुकिंग शुरू कर दी गई है। आप कंपनी की ऑफिशियल 22 हजार रुपए की टोकन मनी देकर बुक कर सकते हैं। कार की डिलीवरी अक्टूबर से शुरू की जाएगी।-

स्वास्थ्य मंत्रालय ने समोसा-जलेबी पर चेतावनी लेबल की खबर को किया खारिज

नई दिल्ली (एजेंसी)। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उसने समोसा, जलेबी या किसी अन्य पारंपरिक खाद्य उत्पाद पर चेतावनी लेबल लगाने का कोई निर्देश नहीं दिया है। यह स्पष्टीकरण उस समय आया जब मंत्रालय की हालिया सलाह को लेकर भ्रम फैल गया था, जिसमें छिपी वसा और अतिरिक्त चीनी के सेवन के प्रति जागरूकता बढ़ाने की बात कही गई थी। पिछले महीने 21 जून को स्वास्थ्य सचिव द्वारा सभी सरकारी विभागों, कार्यालयों और स्वायत्त संस्थानों को एक पत्र जारी किया गया था। इसमें कार्यालयों में स्वस्थ भोजन और जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता बोर्ड लगाने और स्टेशनरी पर स्वास्थ्य संदेश छापने की सलाह दी गई थी। इस सलाह को कुछ लोगों ने समोसा और जलेबी जैसे लोकप्रिय भारतीय स्नैक्स के खिलाफ चेतावनी के रूप में देखा, जिससे सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर बहस शुरू हो गई। जवाब में मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह किसी विशेष खाद्य पदार्थ के खिलाफ निर्देश नहीं है, बल्कि यह मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग जैसी गैर-संचारी बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए एक सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता पहल है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार का उद्देश्य भारत की समृद्ध स्ट्रीट फूड संस्कृति को लक्षित करना नहीं है। लैंसेट जीबीडी 2021 के अनुसार, यदि वर्तमान रुझान जारी रहे, तो 2050 तक भारत में मोटापे से पीड़ित वयस्कों की संख्या 44.9 करोड़ तक पहुंच सकती है।

मिलेजुले संकेतों के दौरान सपाट स्तर पर रहे शेयर बाजार

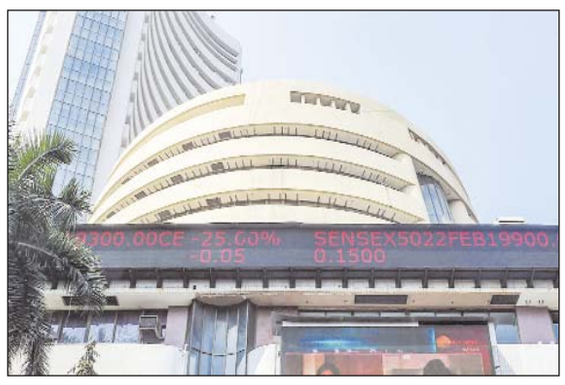

मुंबई (एजेंसी)। वैश्विक बाजारों से मिलेजुले संकेतों की वजह से बुधवार के कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सपाट स्तर पर हुई। सेंसेक्स 139 अंक की गिरावट के साथ 82,431 और निफ्टी 58 अंक की कमजोरी के साथ 25,137 पर कारोबार कर रहा था। शुरुआती कारोबार में मिडकैप और स्मॉलकैप में सपाट कारोबार हो रहा था। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 6 अंक की मामूली गिरावट के साथ 59,605 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 14 अंक की कमजोरी के साथ 19,120 पर था। वहीं शेयर बाजारों में चार दिन से जारी गिरावट मंगलवार को थम गई। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स मंगलावर को 317.45 अंक उछलकर 82,570.91 अंक पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 113.50 अंक की बढ़त के साथ 25,195.80 पर बंद हुआ। सेक्टोरल आधार पर आईटी, पीएसयू बैंक, रियल्टी, मीडिया और सर्विसेज इंडेक्स हरे निशान में थे। ऑटो, फार्मा, एफएमसीजी, एनर्जी, इन्फ्रा, पीएसई और कमोडिटी में दबाव के साथ कारोबार हो रहा था। सेंसेक्स पैक में अदाणी पोर्ट्स, ट्रेंट, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, इंफोसिस, आईटीसी, एचसीएल टेक और बीईएल टॉप गेनर्स थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, इटरनल, टीसीएस और अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप लूजर्स थे। बाजार के जानकारों ने कहा कि पिछले दो महीनों से बाजार एक सीमित दायरे में ही कारोबार कर रहा है। इस दायरे के ऊपरी बैंड से ऊपर, यानी निफ्टी 25500 से आगे, ब्रेकआउट के लिए सकारात्मक ट्रिगर्स की आवश्यकता होती है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का रुख मिला-जुला रहा। टोक्यो, हांगकांग, जकार्ता और बैंकॉक हरे निशान में थे। शंघाई और सियोल लाल निशान में थे। अमेरिका में प्रमुख सूचकांक डाउ जोंस सोमवार को 0.98 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ।

रुपया 22 पैसे टूटकर 85.98 प्रति डॉलर पर खुला

मुंबई (एजेंसी)। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी तथा निर्यात एवं आयात में गिरावट के बीच रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में 22 पैसे टूटकर 85.98 प्रति डॉलर पर आ गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि विदेशी पूंजी के प्रवाह ने हालांकि स्थानीय मुद्रा में भारी गिरावट को रोका। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 86.02 पर खुला।

सोने का भाव 97,400 के पार, चांदी 1,11,750 रुपए के करीब

नई दिल्ली (एजेंसी)। सोने-चांदी के वायदा कारोबार की शुरुआत में बुधवार के कारोबार के दौरान तेजी देखी जा रही है। दोनों के वायदा भाव बुधवार को तेजी के साथ खुले। घरेलू बाजार में सोने के भाव 97,400 रुपये, जबकि चांदी के भाव 1,11,750 रुपये के करीब कारोबार कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार सोने-चांदी के वायदा भाव की शुरुआत गिरावट के साथ हुए। हालांकि बाद में भाव सुधर गए। सोने के वायदा भाव की शुरुआत तेजी के साथ हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का बेंचमार्क अगस्त कॉन्ट्रेक्ट 11 रुपये की तेजी के साथ 97,222 रुपये के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 97,211 रुपये था। इस समय यह 196 रुपये की तेजी के साथ 97,407 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। चांदी के वायदा भाव की शुरुआत तेज रही। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क सितंबर कॉन्ट्रेक्ट 88 रुपये की तेजी के साथ 1,11,574 रुपये पर खुला। पिछला बंद भाव 1,11,486 रुपये था। इस समय यह 269 रुपये की तेजी के साथ 1,11,755 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी के वायदा भाव की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। लेकिन बाद में इनके भाव में तेजी देखी जाने लगी। कॉमेक्स पर सोना 3,330.50 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 3,336.70 डॉलर प्रति औंस था। इस समय यह 4.50 डॉलर की तेजी के साथ 3,341.20 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। सोने के वायदा भाव ने इस साल 3,509.90 डॉलर के भाव पर ऑल टाइम हाई छू लिया है। कॉमेक्स पर चांदी के वायदा भाव 37.98 डॉलर के भाव पर खुले। पिछला बंद भाव 38.11 डॉलर था। इस समय यह 0.02 डॉलर की तेजी के साथ 38.13 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था।

आईपीएल 2026 में आरोन होंगे सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजी कोच

हैदराबाद (एजेंसी)। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल के अगले सत्र के लिए पूर्व तेज गेंदबाज वरुण आरोन को अपना गेंदबाजी कोच बनाया है। वह 2026 सत्र के लिए न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स फ्रैंकलिन की जगह कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। सनराइजर्स ने सोशल मीडिया में लिखा, 'हमारे कोचिंग स्टाफ में एक अच्छा बदलाव हुआ है। हम वरुण का हमारे नए गेंदबाजी कोच के रूप में स्वागत करते हैं। आरोन ने साल 2011 से साल 2015 के बीच भारतीय टीम की ओर से नौ टेस्ट और उतने ही एकदिवसीय मैच खेले थे। आरोन ने अपना अंतिम प्रतिस्पर्धी मैच इसी साल पांच जनवरी को जयपुर में गोवा के खिलाफ झारखंड के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में खेल था। झारखंड के घरेलू टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण में पहुंचने में विफल रहने के बाद इस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया था। इस क्रिकेटर ने पिछले साल चेन्नई में एमआरएफ पेस फाउंडेशन में ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्राथ के साथ एक कोच के रूप में भी काम किया है। आरोन ने एक तेज गेंदबाज के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। वह 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने के कारण सभी की नजरों में आये पर उसी दौरा उभरे उमेश यादव विकेट लेने की अपनी क्षमत के कारण चयनकर्ताओं की पहली पसंद बन गये ओर आरोन पीछे होते गये। उमेश ने जहां देश के लिए 50 से अधिक टेस्ट के साथ ही सीमित ओवरों के कई मुकाबले खेले। वहीं आरोन चोटिल होने के कारण अधिकतर समय बाहर रहे।

टेस्ला के मुंबई में शोरूम खोलने पर आनंद महिंद्रा ने किया स्वागत

मुंबई (एजेंसी)। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने मुंबई में टेस्ला के पहले शोरूम खोलने पर एलन मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला का गर्मजोशी से स्वागत किया है। टेस्ला ने भारत में अपनी आधिकारिक एंट्री कर दी है और मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में पहला शोरूम खोला है। टेस्ला ने अपनी मॉडल वाय कार के दो वेरिएंट लॉन्च किए हैं, जिनकी कीमतें 60.1 लाख रुपये से 67.8 लाख रुपये के बीच हैं। हालांकि, भारत में उच्च आयात शुल्क के कारण ये कारें अन्य देशों के मुकाबले महंगी हैं। टेस्ला की शुरुआत मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम में होगी, और डिलीवरी 2025 के अंतिम महीनों में शुरू होगी।

आनंद महिंद्रा ने इस प्रतिस्पर्धा को सकारात्मक रूप में लिया और इसे इनोवेशन को आगे बढ़ाने वाला बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारत में आपका स्वागत है एलन मस्क और टेस्ला दुनिया के सबसे बड़े ईवी अवसरों में से एक अब और भी रोमांचक हो गया है। प्रतिस्पर्धा इनोवेशन को जन्म देती है, और आगे एक लंबा रास्ता है। चार्जिंग स्टेशन पर मुलाकात का इंतजार रहेगा। बता दें कि टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार शुरुआत में केवल मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम में उपलब्ध होगी। इसकी डिलीवरी 2025 के अंतिम महीनों में दी जाएगी। मुंबई के बाद अगला शोरूम दिल्ली में खोले जाने की योजना है।

क्रिकेटर यश दयाल की गिरतारी पर रोक लगी

प्रयागराज (एजेंसी)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को क्रिकेटर यश दयाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यौन शोषण के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की पीठ ने इस क्रिकेटर की उस याचिका पर यह आदेश पारित किया जिसमें उन्होंने मामले में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया था। इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अदालत ने यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। इससे पहले एक युवती ने इस क्रिकेटर के खिलाफ शारीरिक ओर मानसिक शोषण के मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इसमें कहा गया था कि इस क्रिकेटर ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। इस युवती के अनुसार वह इस क्रिकेटर के साथ पांच साल से रिलेशनशिप में थी और इस दौरान उसने शादी का वादा किया था पर बाद में उसने धोखेबाजी कर दी।

गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम थाना में शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें इसयुवती ने यश दयाल पर यौन शोषण का भी आरोप लगाया था। इस युवती ने यह भी दावा किया है कि क्रिकेटर यश दयाल शादी करने का उसका प्रस्ताव टालता रहा और अंत में उसे पता चला कि यश दयाल का अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध है। इस मामले की शिकायत पहले उसने मुख्यमंत्री के ऑनलाइन शिकायत निपटान पोर्टल पर की थी।

करुण नायर पर गिर सकती है गाज, चौथे टेस्ट में शायद ही जगह मिले

लॉर्ड्स (एजेंसी)। भारतीय टीम की तीसरे टेस्ट में हार के साथ ही अब अगले मैच में बदलाव करने का दबाव कप्तान और कोच पर रहेगा। इसका कारण है कि भारतीय बल्लेबाज तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में असफल रहे। ऐसे में कुछ खिलाड़ियों की जगह खतरे में आ गयी है। इसमें सबसे पहला नाम आठ साल बाद वापसी कर रहे बल्लेबाज करुण नायर का हो सकता है। करुण अब तक हुए तीनों की मैचों में विफल रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें बाहर किया गया तो उनका करियर समाप्त होना तय है। वहीं ये भी कहा जा रहा है जब सभी खिलाड़ी बल्लेबाजी में विफल रहे हैं तब केवल एक को ही निशाना कैसे बनाया जा सकता है।

भारतीय टीम तीसरे मुकाबले में 193 रन का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी और 170 रन पर ही सिमट गयी। इससे टीम 5

मैचों की सीरीज में 1-2 से पिछड़ गया है। वहीं टीम में 8 साल बाद लौटने वाले करुण से विशेष तौर पर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी पर वह उसमें विफल रहे। उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर अब तक खेले 3 टेस्ट की 6 पारियों में 131 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका सबसे ज्यादा स्कार 40 रन रहा है। वह सभी शीर्ष बल्लेबाजों से कम रन बना पाये हैं। जहां अब तक कप्तान शुभमन गिल 607 और उप कप्तान ऋषभ पंत 425 रन व केएल राहुल के नाम 375, रवींद्र जडेजा के नाम 327 और यशस्वी जायसवाल के नाम 233 रन हैं। वहीं करुण 131 रन ही बना पाये हैं। ऐसे में बल्लेबाजी लाइनअप में कोई बदलाव होने पर करुण नायर को ही हटाया जाएगा। वहीं पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान और दीप दासगुप्ता का मानना है कि आपको भविष्य को देखते हुए युवा खिलाड़ियों को अवसर देने होंगे। ऐसे में अगर आप 21 साल के खिलाड़ी साई सुदर्शन)को लेकर आए हैं तो उसे अधिक से अधिक अवसर दीजिए। वहीं पठान ने कहा, 'जहां तक मैं जानता हूं कोच गौतम गंभीर ने करुण को पूरा अवसर देने का वादा किया है। ऐसे में संभावना यही है कि करुण को अभी और अवसर मिलेंगे.' वहीं इस मामले में अन्य क्रिकेट प्रशंसकों की अलग-अलग राय है। जहां कई प्रशंसक करुण को और मौका दिए जाने के पक्ष में हैं. कई फैंस ऐसे भी हैं, जिन्हें लगता है कि करुण को पर्याप्त अवसर दिये जा चुके हैं और अब बचे हुए अवसर युवाओं को देने चाहिये। अब देखना है कि करुण टीम में बरकरार रहते हैं या बाहर जाते हैं।

स्टार्क ने भारतीय ऑलराउंडर का 19 साल पुराना रिकार्ड तोड़ा

किंग्स्टन (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने यहां वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट में घातक गेंदबाजी करते हुए जहां अपनी टीम को बड़ी जीत दिलायी। वहीं 19 साल पुराना भारतीय टीम के तेज गेंदबाज इरफान पठान का रिकार्ड भी तोड़ दिया। स्टार्क ने तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी के पहले ही ओवर में ही जॉन कैंपबेल, केवलॉन एंडरसन और ब्रैंडन किंग को आउट कर दिया। कैंपबेल और किंग बिना कोई रन बनाए आउट हुए जबकि एंडरसन चार गेंद ही खेल पाये। साल 2006 में कराची के नेशनल स्टेडियम में भारत-पाकिस्तान टेस्ट के पहले ओवर में भी इरफान पठान ने तीन गेंदों में तीन विकेट लिए थे। उस मैच में पठान ने पाकिस्तान की पहली पारी के पहले ओवर की चौथी गेंद पर सलमान बट को चार गेंदों पर डक आउट कर अपना विकेट खाता खोला और फिर यूनिस खान को गोल्डन डक किया था। इरफान ने मोहम्मद यूसुफ को आउट कर पहले ओवर की आखिरी गेंद पर अपनी हैट्रिक पूरी की। पहले ओवर में तीन विकेट लेने के बाद स्टार्क ने अपने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर मिकाइल लुईस को 4 रन पर आउट किया और तीसरी गेंद

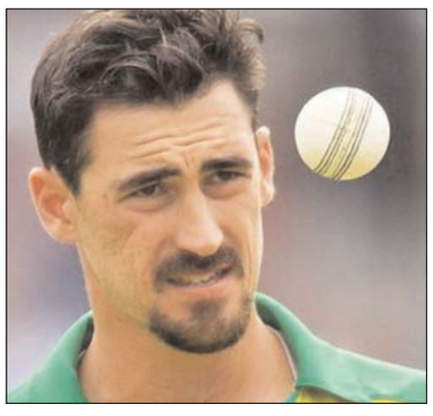

पर शाई होप का विकेट लेकर पांच विकेट पूरे किए। उन्होंने अपने पांच विकेट लेने के लिए केवल 15 गेंदों का इस्तेमाल किया। केवल 15 गेंद फेंककर उन्होंने 5 विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। इससे कम गेंदों पर किसी गेंदबाज ने कभी किसी टेस्ट की एक पारी में 5 विकेट नहीं लिए थे।

2028 लास एंजिल्स ओलंपिक की शुरुआत 14 जुलाई से होगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के अनुसार ओलंपिक 2028 खेल 14 जुलाई को शुरु होकर 30 जुलाई तक चलेंगे। उद्घाटन समारोह 14 जुलाई को होगा। वहीं समापन समारोह 30 जुलाई को होगा। इसमें लंबे समय बाद वापसी कर रहे क्रिकेट के मुकाबले इसके प्रारंभ होने से कुछ दिन पहले ही शुरू हो जाएंगे। क्रिकेट के मुकाबले 12 जुलाई से शुरू होकर 29 जुलाई तक खेले जाएंगे। 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक में भारत को क्रिकेट के अलावा कुश्ती, निशानेबाजी , एथलेटिक्स, हॉकी, बैडमिंटन में पदक मिलने की अधिक संभावना है। क्रिकेट -6 टीमों वाला ये टूर्नामेंट 12 से 20 जुलाई तक फेयरग्राउंड्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसमें पुरुष टीम अपना पहला मैच 22 जुलाई को खेलेगी। कुश्ती -कुश्ती के मुकाबालों का आयोजन 24 से 30 जुलाई तक लॉस एंजिल्स कन्वेंशन सेंटर हॉल 2 में आयोजित होगा। निशानेबाजी - निशानेबाजी इवेंट 15 जुलाई से शुरू होकर लॉन्ग बीच टारगेट शूटिंग हॉल में 25 जुलाई तक चलेंगे। एथलेटिक्स - एथलेटिक्स इवेंट 15- 24 जुलाई तक कोलिजीयम में आयोजित होंगे। हॉकी -लॉस एंजलिस खेलों में हॉकी के मुकबाले 12 से 29 जुलाई के बीच कार्सन फील्ड पर खेले जाएंगे। बैडमिंटन - गैलेन सेंटर में होने वाले इस आयोजन में 15 से 24 जुलाई तक मुकाबले होंगे। वेटलिफ्टिंग - वेटलिफ्टिंग के इवेंट पीकॉक थियेटर में 24 से 29 जुलाई के बीच होंगे। बॉक्सिंग - बॉक्सिंग के इवेंट 15 से 30 जुलाई के बीच होंगे।

अपनी निजी निजी ज़िंदगी को लेकर चर्चाओं में रही हैं साइना और सानिया

नई दिल्ली (एजेंसी)। टेनिस स्टार साइना मिर्जा और बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र की दिग्गज खिलाड़ी हैं पर कई लोग इन दोनो के मिलते जुलते नामों के कारण संशय में आ जाते हैं। जहां साइना बैंडमिंटन खिलाड़ी हैं, वहीं सानिया टेनिस खिलाड़ी है के तौर पर जानी जाती हैं। सानिया ने फरवरी 2023 में दुबई टेनिस चैंपियनशिप के बाद पेशेवर टेनिस को अलविदा कह दिया था। सानिया मिर्जा का जन्म मुंबई में हुआ था पर वे पली-बढ़ी हैदराबाद में थीं, जबकि साइना नेहवाल हरियाणा की रहने वाली हैं। ये दोनो ही अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर भी चर्चाओं में रही है। हरियाणा के हिसार की साइना नेहवाल ने हैदराबाद के सेंट ऐनी कॉलेज, मेहदीपट्टनम से 10वीं पास की थी। बैडमिंटन में व्यस्तता के कारण वह कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई थीं। साइना ने कई अंतरराष्ट्रीय खिताब जीते और भारत को बैडमिंटन में ग्लोबल पहचान दिलाई। वहीं दसूरी ओर हैदराबाद

से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद सानिया ने सेंट मैरी कॉलेज, हैदराबाद से ग्रेजुएशन किया। साल 2008 में उन्हें चेन्नई के एमजीआर शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान से डीलिट की मानद उपाधि भी मिली. सानिया की शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की शादी 2010 में हुई थी और 2018 में उनके बेटे इजहान मिर्जा मलिक का जन्म हुआ था। 2024 में सानिया ने शोएब से तलाक ले लिया था। वहीं, साइना नेहवाल ने साल 2018 में शादी की थी और करीब 7 सालों बाद यानी 2025 में अपने पति पारुपल्ली कश्यप से तलाक की कर दी।

साइना कमाई के मामले में भी पीछे नहीं

हैदराबाद (एजेंसी)। अनुभवी महिला बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल खेल के साथ ही कमाई के मामले में भी पीछे नहीं है। साइना अपनी स्टाइलिश जीवनशैली के लिए भी जानी जाती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ओलंपिक में पदक विजेता होने के साथ ही विश्व की नंबर एक खिलाड़ी रही साइना की संपत्ति तकरीबन 36 से 40 करोड़ रुपये की है। वह देश की सबसे धनी बैडमिंटन खिलाड़ियों में शामिल हैं। में गिनी जाती हैं। उनकी कमाई टूर्नामेंट, ब्रांड एंडोर्समेंट और रॉयल्टी से आती है। इसके साथ ही उनके पास लग्जरी कार ओर आलिशान घर हैं। साइना ने 2015 में हैदराबाद में 4.6 करोड़ रुपये का एक आलीशान घर खरीदा था। साथ ही उनके कलेक्शन में बेहतरीन कारें भी शामिल हैं।

हाथ पर लिखा- आरक्षक आशीष के पीछे जान दे रहा, परिजनों ने शव रख किया चक्काजाम

पार्क में पेड़ पर लटका मिला नपा कर्मचारी का शव

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। सतना के नागौद कस्बे में बुधवार सुबह नगर परिषद के कर्मचारी सुदामा कोरी का शव रामना ग्राउंड स्थित पार्क में पेड़ पर लटका मिला। घटना के विरोध में परिजनों ने नागौद-जसो मार्ग पर जाम लगा दिया और देवेंद्रनगर थाने में पदस्थ आरक्षक आशीष कोरी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। करीब 1.30 घंटे बाद थाना प्रभारी की समझाइश पर माने। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी हैं।

जानकारी के अनुसार, सतना जिले के नागौद निवासी सुदामा कोरी नगर परिषद के रामना ग्राउंड स्थित पार्क में ड्यूटी करते थे। परिजनों ने बताया कि बुधवार सुबह वह रोजाना की तरह पार्क में ड्यूटी के लिए गए, इसके बाद उनका शव पार्क में शीशम के पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका मिला।

स्थानीय लोगों ने परिजनों को सूचना दी, इसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। शव को नीचे उतारने पर मृतक के हाथ पर पन्ना जिले के देवेन्द्रनगर थाने में पदस्थ आरक्षक आशीष कोरी का नाम लिखा मिला।

कर्मचारी सुदामा कोरी के हाथ पर पेन से लिखा था- देवेन्द्रनगर के आशीष कोरी के पीछे जान दे रहा हूं, मेरे घर-परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए।

मुख्यमंत्री के ससुर के निधन पर उप मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के ससुर ब्राम्हानंद यादव का निधन उत्तरप्रदेश में उनके गृह ग्राम सुलतानपुर में हो गया हैं। उनका पार्थिव शरीर पैतृक निवास रीवा स्थित संजय नगर लाया गया। स्वर्गीय यादव के निधन पर उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल उनके निवास पहुंचकर पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं शोक संतप्त परिजनों से भेंट कर अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व. यादव ने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं अनुषांगिक संगठनों में कार्य करते हुए मां भारती की सेवा में अर्पित किया। इस दुःख की घड़ी में हम सभी की संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करें।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल स्वर्गीय यादव के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए। अंतिम संस्कार बीहर नदी के किनारे बदरिया मुक्तिधाम में किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। अंतिम संस्कार में पूर्व महापौर वीरेन्द्र गुप्ता, रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद, आईजी गौरव राजपूत, डीआईजी राजेश सिंह, एसपी विवेक सिंह, आयुक्त नगर निगम डॉ. सौरभ सोनवणे सहित अन्य अधिकारी और बड़ी संख्या में परिवारजन तथा रिश्तेदार उपस्थित रहे।

बाढ़ से बचाव के लिये उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हुआ विचार मंथन

रीवा में नदी के ग्रीन वेल्ट में अतिक्रमण को रोकते हुए नदी के चौड़ीकरण की कार्ययोजना बनायें

उप मुख्यमंत्री ने बाढ़ से बचाव के लिए दिये आवश्यक निर्देश

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। रीवा शहर में गत दिनों अत्यधिक वर्षा के कारण जलभराव होने से कई मोहल्ले प्रभावित हुए थे और बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई थी। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट में बाढ़ से बचाव के लिये विचार मंथन किया गया तथा वर्ष 2016 की बाढ़ के उपरांत सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ से बचाव के लिये बनाए गये प्रोजेक्ट में सुझाये गये बिन्दुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बाढ़ से बचाव के लिये आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि रीवा में नदी के किनारे ग्रीन वेल्ट में अतिक्रमण को रोकें ताकि नदी का प्रवाह अवरूद्ध न हो। उन्होंने उन्नत पुल से आगे करहिया की तरफ नदी के प्रवाह में पद्मधर कालोनी से लगे किनारे को दोनों तरफ चौड़ा करने की कार्ययोजना पर कहा कि शासकीय भूमि के अतिरिक्त निजी भूमि स्वामियों की सहमति से चौड़ीकरण कार्य कराया जाय ताकि बार बार आने वाली बाढ़ से मुक्ति मिले। उन्होंने करहिया पुल के नीचे बने वक्से के अवरोध को हटाने तथा चौड़ाई के बाद चैनलिंग करने के निर्देश दिये। शुक्ल ने कहा कि उन्नत पुल से करहिया पुल तक तथा उससे आगे वायपास पुल तक नदी को चौड़ा किये जाने की कार्ययोजना बनाई जाय। नदी के अपस्ट्रीम में पूर्व के निर्मित तीन बांधों के वेस्ट वेयर, बंड को दुरूस्त करने तथा गेट बंद करने की कार्ययोजना भेजें ताकि उन बांधों में वर्षा का जल संग्रहित हो और नदी में ज्यादा पानी न आये और बाढ़ की स्थिति निर्मित न हो।

बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि एलए का प्रस्ताव बनायें तथा बांधों के वेस्ट वेयर, बंड को दुरूस्त करने की भी कार्ययोजना प्रस्तुत करें। इस अवसर पर पूर्व मुख्य अभियंता आर.एन. शर्मा ने बाढ़ रोकने के लिये बनाये गये प्रोजेक्ट का प्रस्तुतीकरण कर आवश्यक सुझाव दिये। बैठक में अध्यक्ष नगर निगम व्यंकटेश पाण्डेय, आयुक्त नगर निगम डॉ. सौरभ सोनवणे, एसडीएम हुजूर वैशाली जैन, विवेक दुबे, राजेश पाण्डेय सहित सिंचाई विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

सतना में डॉक्टर ने गर्भपात कराने कहा था, परिजन ने सोनोग्राफी कराई तो स्वस्थ दिखा

सरकारी अस्पताल में बताया मृत, प्राइवेट हॉस्पिटल में जन्मा स्वस्थ्य बच्चा

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। सतना के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने गर्भस्थ शिशु को मृत बता दिया। महिला और उसके पति को बेबी टर्मिनेट कराने की सलाह दे डाली। लेकिन परिवार नहीं माना। प्राइवेट क्लिनिक से सोनोग्राफी कराई। इसमें बच्चा पूरी तरह स्वस्थ दिखा।

परिजन महिला को लेकर निजी अस्पताल पहुंचे। यहां डिलीवरी के बाद स्वस्थ बच्चा जन्मा। मामला सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय जिला अस्पताल का है।

रामपुर बघेलान में चकेरा गांव निवासी दुर्गा द्विवेदी (24) को सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात 2 बजे अमरपाटन सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आशा कार्यकर्ता शीला तिवारी भी उनके साथ थी। प्रसव पीड़ा बढ़ने के कारण यहां से सुबह 4 बजे उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

जिला अस्पताल में मंगलवार सुबह 9 बजे सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने डॉपलर से जांच की। बताया कि शिशु की धड़कन नहीं मिल रही है। सोनोग्राफी में भी नकारात्मक परिणाम आने पर डॉक्टर ने दवा से गर्भपात की सलाह दी।

दुर्गा के पति राहुल द्विवेदी ने बताया- पत्नी का नाम हाई रिस्क में पहले से था। सुबह साढ़े 7 बजे जिला अस्पताल पहुंचने पर ड्यूटी डॉक्टर ने ब्लड चेकअप कराने को कहा। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की धड़कन नहीं चल रही है। सोनोग्राफी में भी बच्चे का कोई मूवमेंट नहीं मिला और न ही हार्टबीट सुनाई दी। हालांकि, दिल की जांच में डॉक्टर ने बच्चे की धड़कन चलने की पुष्टि की, लेकिन जिला अस्पताल की डॉक्टर ने अबॉर्शन की सलाह दे दी।

पहला प्रसव होने के कारण परिजन से सलाह-मशविरा किया। राहुल पत्नी को भरहुतनगर के एक डायग्नोस्टिक सेंटर ले गए। यहां सोनोग्राफी कराई। इसमें शिशु स्वस्थ पाया गया। इसके बाद निजी नर्सिंग होम में सीजेरियन ऑपरेशन से साढ़े तीन किलो का बच्चा पैदा हुआ।

सफल डिलीवरी कराने वाली डॉ. मीनाक्षी अग्रवाल ने बताया- हमारे पास पेशेंट आया तो उसकी सोनोग्राफी कराई गई। सब कुछ नॉर्मल मिलने पर ऑपरेशन किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में मेटरनिटी विंग की प्रभारी डॉ. मंजू सिंह ने कहा- डॉपलर और सोनोग्राफी में गर्भस्थ शिशु की धड़कन नहीं मिल रही थी। इसी कारण डॉक्टर ने बच्चे को मृत बताया था।

शासन की योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राहियों को लाभ दिलाने में सीएससी की भूमिका महत्वपूर्ण

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम व्यक्ति तक लाभ दिलाने में कामन सर्विस सेंटर की भूमिका महत्वपूर्ण है। सीएससी द्वारा हितग्राहियों से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति कराकर उन्हें योजनाओं का लाभ लेने का पात्र बनाया जाता है। उन्होंने कामन सर्विस सेंटर के ग्रामीण क्षेत्र के इन्टरप्रेन्योरशिप को अपनी शुभकामनाएँ दी तथा अपेक्षा की कि वह जनकल्याण के कार्य में सतत क्रियाशील रहे। कृष्णा राजकपूर आडिटोरियम में कामन सर्विस सेंटर के 16वें स्थापना दिवस पर आयोजित संभाग स्तरीय कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएससी

के माध्यम से लोगों को आधार से लेकर अन्य योजनाओं का लाभ दिलाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति जो शासन की योजनाओं का लाभ ले पाने में आगे नहीं आ पाते उन्हें सीएससी योजनाओं का लाभ लेने का पात्र बनाया जाता है। शुक्ल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अनेक जनकल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही है। इनमें आगे आकर लाभ लेना आवश्यक है। लाड़ली बहना योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है जिसके माध्यम से प्रदेश की लगभग आधी आबादी आर्थिक तौर पर सशक्त हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में विश्व में तीसरे स्थान पर होगी।

कार्यक्रम में विधायक सिरमौर दिव्यराज सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी, महाप्रबंधक केन्द्रीय सहकारी बैंक ज्ञानेन्द्र पाण्डेय सहित सीएससी के प्रभारी उपस्थित रहे।

कृषि विकास संबंधी कार्यशाला आज

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन मण्डी बोर्ड द्वारा कृषि अवसंरचना निधि की निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। इस समिति में कृषि, सहकारिता, उद्यानिकी, पशुपालन, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, मध्यप्रदेश आजीविका मिशन, मछली पालन विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है। इनकी संभागीय प्रशिक्षण कार्यशाला 17 जुलाई को माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय सभागार में सुबह 10 बजे से आयोजित की जा रही है। इसमें संभाग के सभी जिलों के संबंधित विभागों के लगभग दो सौ अधिकारी शामिल होंगे।

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनायें

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश देते हुए कहा है कि प्रतिदिवस ओपीडी की संख्या कम से कम 50 हो तथा सभी चिकित्सक व स्टाफ नियत समय तक प्रतिदिवस अनिवार्यतः स्वास्थ्य केन्द्रों में उपस्थित रहें।

उप मुख्यमंत्री ने अमहिया रीवा स्थित निवास में आयोजित बैठक में विधानसभा रीवा क्षेत्र अन्तर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केन्द्रों में ब्लड कलेक्शन करते हुए टेली मेडिसिन की भी सेवाएँ मरीजों को उपलब्ध कराई जांय। उन्होंने कहा कि ओपीडी बढ़ाने तथा टेली मेडिसिन की सुविधा से ग्रामीणों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ही इलाज मिल सकेगा और जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़ कम होगी। उन्होंने मेडिकल आफीसर्स से पूरी तन्यता से गरीबों की सेवा करने की अपेक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य केन्द्रों में बाउण्ड्री बाल निर्माण तथा साफ-सफाई के संबंध में जानकारी ली। बैठक में चिकित्सक व संबंधित जन उपस्थित रहे।

युवा संगम के तहत रोजगार मेले में 191 युवाओं को मिला रोजगार

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। युवा संगम कार्यक्रम के तहत शिक्षण संस्थाओं में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर प्रतिभा पाल के मार्गदर्शन में संभागीय आईटीआई रीवा में रोजगार मेला आयोजित किया गया। इसमें 346 आवेदकों ने पंजीयन कराया। मेले में शामिल 10 कंपनियों ने 191 युवाओं का चयन किया। उप संचालक रोजगार अनिल दुबे ने बताया कि रोजगार मेले में बजाज मोटर्स लिमि. हरिद्वार ने 20, धूत ट्रान्समिशन औरंगाबाद ने 34, आई.डब्लू.आई. लि. ने 20, विजन इंडिया प्रा. लि. ने 26, ग्रोफास्ट प्रा. लि. जबलपुर ने 13, प्रगतिशील एग्रोटेक प्रा. लि. रीवा ने 12, एचडीएफसी लाइफ इश्योरेन्स कंपनी रीवा ने 21 तथा प्रगतिशील बायोटेक प्रा. लि. रीवा ने 45 युवाओं का चयन किया। रोजगार मेले के सफल आयोजन में जिला रोजगार कार्यालय तथा आईटीआई के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

कमिश्नर ने स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की

शिशुओं और महिलाओं की स्वास्थ्य रक्षा के लिए मिलकर प्रयास करें

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि शिशुओं और महिलाओं की स्वास्थ्य रक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग मिलकर प्रयास करें। ग्राम स्तर से लेकर संभाग स्तर तक दोनों विभाग समन्वित प्रयास करेंगे तभी बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार होगा। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर पर नियंत्रण हो सकेगा। दोनों विभागों के हितग्राही तथा लक्ष्य समूह एक हैं। इसलिए दोनों को समन्वय के साथ प्रयास करने की आवश्यकता है। हर गर्भवती महिला का अनिवार्य रूप से पंजीयन कराकर जाँच सुनिश्चित करें। हाईरिस्क गर्भावस्था वाली महिलाओं को चिन्हित करके समय पर अस्पताल में भर्ती कर समुचित उपचार की सुविधा दें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा बीएमओ स्वास्थ्य सेवाओं, उपचार व्यवस्था एवं पोर्टल में

जानकारी दर्ज करने की नियमित समीक्षा करें। गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत पंजीयन कर 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कमिश्नर ने बैठक में बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर सिंगरौली जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला स्वास्थ्य अधिकारी की एक वार्षिक वेतनवृद्धि अवरूद्ध करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने रीवा शहरी क्षेत्र, हनुमना, बैढ़न, चितरंगी तथा सोहावल के बीएमओ की भी वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश दिए।

बैठक में कमिश्नर ने कहा कि चिन्हित सभी डिलेवरी प्वाइंट में प्रसव की पूरी सुविधा रखें। शत-प्रतिशत प्रसव अनिवार्य रूप से अस्पतालों में हों। घर में प्रसव की जानकारी मिली तो जिम्मेदारी तय करके कार्यवाही की जाएगी। महिलाओं और बच्चों में खून की कमी के कारणों का विश्लेषण करके उनका समुचित उपचार सुनिश्चित करें। भोजन में मुनगा, नींबू, पालक, गुड़, महुआ, दाल, मोमफली जैसे स्थानीय वस्तुओं का समुचित उपयोग करके भी अच्छा पोषण मिल जाता है। इस संबंध में अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं के घर हर सप्ताह भ्रमण करें। उनके घर में माह में एक बार गर्भवती महिला के साथ में भोजन करके अच्छे पोषण के संबंध में जागरूक करें। दस्तक अभियान 22 जुलाई से 22 अगस्त तक चलाया जाएगा। दोनों विभाग मिलकर नवजात से पाँच साल तक के बच्चों की पूरी जाँच करें। कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन करके उन्हें समुचित उपचार और पोषण दें। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर की प्रत्येक घटना का पूरा विश्लेषण और ऑडिट करें। दोनों विभाग के जिलाधिकारी विकासखण्ड स्तर पर संयुक्त बैठक करके दोनों विभागों के योजनाओं की समीक्षा करें।

बैठक में कमिश्नर ने कहा कि क्षय मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य इसी वर्ष दिसम्बर माह तक पूरे करने के प्रयास करें। बैठक में सिकल सेल एनीमिया, परिवार कल्याण अभियान, टीकाकरण अभियान, पोषण पुनर्वास केन्द्र में बच्चों की भर्ती तथा वर्षाजनित रोगों से बचाव और उपचार के प्रबंधों की समीक्षा की गई। कमिश्नर ने महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि आंगनवाड़ी केन्द्रों से पोषण आहार के वितरण की नियमित मॉनीटरिंग करें। किराये के भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों को आसपास के शासकीय भवनों में शिफ्ट करने के प्रयास करें। कम पोषित बच्चों के चिन्हांकन के लिए अभियान चलाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बैठक में लाड़ली बहना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना तथा अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई। कमिश्नर ने कहा कि सभी आंगनवाड़ी केन्द्र परिसरों तथा स्वास्थ्य विभाग की संस्थाओं में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधे रोपित करें। वृक्षारोपण में मुनगा, नींबू, आम, आंवला के पौधे रोपित कराएं। बैठक में संयुक्त आयुक्त सुदेश मालवीय, संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉ एमएल गुप्ता, संभाग के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी उपस्थित रहे।

आईटीआई में प्लेसमेंट ड्राइव 21 को

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। संभागीय आईटीआई रीवा में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन 21 जुलाई को सुबह 10 बजे से किया गया है। इसका आयोजन आईटीआई के वर्ष 2023, 2024 तथा 2025 अंतिम वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों के अप्रेंटिस पद के लिए किया जा रहा है। इस संबंध में प्राचार्य आईटीआई ने बताया कि इसमें 18 वर्ष से 25 वर्ष की आयु के फिटर, बेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, व्यवसाय के प्रशिक्षणार्थी भाग ले सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जायेगा। प्लेसमेंट ड्राइव में जिंदल सा लिमिटेड ताल मुंद्रा कच्छ गुजरात की कंपनी शामिल हो रही है। इच्छुक प्रशिक्षणार्थी अपने समस्त दस्तावेज एवं पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ के साथ नियत तिथि पर उपस्थित होकर प्लेसमेंट ड्राइव में शामिल हो सकते हैं।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा मीडिया प्रकाशन रीवा से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय प्रभात बिहार कॉलोनी सतना से प्रकाशित, संपादक संदीप द्विवेदी आर.एन.आई नं.एमपीएचआईएन/2021/81683
प्रधान कार्यालय रीवा (सिटी कार्यालय चक्रधर सिटी सेंटर रीवा) फोन. नं. 9407132714, 7974467831 Mediaauditor1@gmail.com पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार, सभी विवादो का न्याय क्षेत्र रीवा होगा।